

[2023] 4 एस. सी. आर 680

अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया

बी.

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

(2023 की सिविल अपील संख्या 1308)

20 फरवरी, 2023

[बी. रामसुब्रमणियन और बी. बी. नागरत्ना, जे. जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.112-विवाह के दौरान जन्म, निर्णायक

वैधता का प्रमाण-नाबालिग बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण-के तहत परिस्थितियाँ

जिन्हें निर्देशित किया जा सकता है-सिद्धांत गिने गए।

भारत का संविधान-निजता का अधिकार-का डीएनए परीक्षण

बच्चे-आयोजित: बच्चों को यह अधिकार है कि अदालत के समक्ष उनकी वैधता पर तुच्छ सवाल न उठाए जाएं-यह निजता के अधिकार की एक अनिवार्य विशेषता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872। 112 - अनुमान यू/एस। 112 - अनुपस्थिति।

इस तरह की धारणा को हटाने के लिए "गैर-पहुँच" की याचिका का प्रभाव-प्रतिवादी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की-के अधीन आने का निर्देश मांगा गया

बेटा डी. एन. ए. परीक्षण के लिए-स्वीकृत-की शुद्धता-आयोजित: एक बार जब किसी विवाह को वैध माना जाता है, तो एक मजबूत धारणा होती है कि उस विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हैं।

धारणा का खंडन केवल इसके विपरीत मजबूत, स्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है-पितृत्व की निर्णायक धारणा।

वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे का यह कहना है कि बच्चा पति का है और इसका खंडन केवल डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है-खंडन करने के लिए आवश्यक बात यह है कि उस समय तक पहुँच न होने का प्रमाण है जब बच्चा पैदा हो सकता था, यानी उसकी गर्भधारण के समय-हालाँकि, वर्तमान मामले में, पति द्वारा इस धारणा को दूर करने के लिए गैर-पहुँच के रूप में कोई याचिका नहीं उठाई गई थी। s.112-इसलिए, बेटे पर डीएनए परीक्षण करने के निर्देश को सही ठहराने के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है।

कॉल रिकॉर्डिंग/प्रतिलेखों का कब्जा, और अपीलार्थी की दैनिक डायरी जो उसकी बेवफाई की ओर इशारा करती है, इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलार्थी के व्यभिचार के बारे में सच्चाई का पता लगाने के

लिए डी. एन. ए. परीक्षण एकमात्र संभावित तरीका होगा-उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और परिवार न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

-

680 ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[पर वी. रामसुब्रमण्यन, जे. (सहमति)]-डी. एन. ए. परीक्षण की अनुमति के सवाल का विश्लेषण बच्चे के चश्मे से किया जाना है न कि माता-पिता के चश्मे से।

यह दिखाने के लिए एक मोहरे के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए कि बच्चे की माँ व्यभिचार में रह रही थी-यह हमेशा प्रतिवादी के लिए खुला है-पति अन्य सबूतों द्वारा पत्नी के व्यभिचारी आचरण को साबित करने के लिए, लेकिन, बच्चे की पहचान के अधिकार का त्याग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साक्ष्य अधिनियम, 1872। 112 , 114 चित्रण (एच)-क्या एक प्रतिकूल धारणा चित्रण (एच) से एस के तहत खींची जा सकती है। 114 , पत्नी के व्यभिचारी आचरण के बारे में यदि वह बच्चे के डीएनए परीक्षण के निर्देश का पालन करने से इनकार करती है-प्रतिवादी-पति ने दावा किया कि उसे बच्चे के कथित व्यभिचारी आचरण का पता चला है।

अपीलार्थी-दूसरे बेटे के जन्म के 3 साल बाद पत्नी ने व्यभिचार के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की-विषय के लिए निर्देश मांगा

डी. एन. ए. परीक्षण के लिए दूसरे बेटे को अनुमति दी गई-अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई-दीपानविता रॉय मामले पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वह बच्चे की वैधता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि अपीलार्थी के खिलाफ व्यभिचार का आरोप लगा रहा है और इसलिए, बच्चे को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन करने से इनकार करने पर, एक अनुमान यू / S.114 (h) को उसके खिलाफ खींचा जा सकता है-आयोजित: इस धारा के तहत अनुमान विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है-इसके अलावा, दीपानविता रॉय में तथ्य ऐसे थे

बाध्यकारी, ताकि एक डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश को उचित ठहराया जा सके क्योंकि उसमें पति ने गैर-पहुंच का एक विशिष्ट अनुरोध लिया था, वर्तमान मामले के विपरीत-तत्काल मामले में, बेटे के पितृत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है क्योंकि स्वीकार किया जाता है कि वह पक्षों के निरंतर सहवास के दौरान पैदा हुआ था और इस प्रकार एक वैध विवाह के निर्वाह के दौरान-तथ्यों पर, अपीलार्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। S.114 अपने बेटे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने से इनकार करने पर-व्यभिचार के आरोप को प्रतिवादी डी हॉर्स द्वारा बेटे के पितृत्व के मुद्दे को साबित करना होगा-[प्रति वी. रामसुब्रमण्यन, जे. (सहमति)] - S.114 का इससे कोई लेना-देना नहीं है, और न ही एस द्वारा निपटाई गई वैधता के निर्णायक प्रमाण के संबंध में है। 112 - दोनों एस। 112 और एस। 114 विभिन्न खंडों के अंतर्गत आते हैं। 114 (ज) उस मामले में कोई आवेदन नहीं है जहां एक माँ बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने से इनकार करती है-इसके अलावा, तथ्यों पर, प्रतिवादी की पत्नी से उस समय तक संपर्क था जब बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद भी तीन साल की पूरी अवधि के लिए-इसलिए, निर्णायक प्रमाण यू / S.112 वास्तव में इस मामले में काम में आया है-प्रत्यर्थी का तर्क है कि जिसे लागू करने की मांग की गई है वह केवल S है। 114 (ज) और एस नहीं। 112 अस्वीकार कर दिया जाता है।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.112-बच्चे की वैधता का सवाल, सबूत का बोझ-आयोजित: से एस। 112 वैधता की धारणा बनाता है कि विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है, बच्चे की वैधता पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति पर बोझ डाला जाता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872। 112 - अंतर्निहित सिद्धांत-"पहुँच", "गैर-पहुँच"-अर्थ-आयोजित: अंतर्निहित सिद्धांत एस। 112 यह बच्चे के पितृत्व के बारे में अनुचित जांच को रोकने के लिए है

जिनके माता-पिता की प्रासंगिक समय पर एक-दूसरे तक "पहुँच" या "गैर-पहुँच" थी, इसका मतलब वास्तविक सह-निवास नहीं है, बल्कि इसका मतलब यौन अवसरों का "अस्तित्व" या "अस्तित्वहीन" है।

संबंध - s.112 जन्म के समय को महत्वपूर्ण पहलू के रूप में संदर्भित करता है न कि गर्भधारण के समय के रूप में-गर्भधारण का समय केवल यह देखने के लिए प्रासंगिक है कि पति की पत्नी तक पहुँच थी या नहीं-निर्णायक धारणा के संचालन को प्रासंगिक समय पर गैर-पहुँच साबित करके टाला जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून-अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधियाँ-बाल अधिकारों पर सम्मेलन-एक बच्चे के सर्वोत्तम हित-गोपनीयता, स्वायत्तता और बच्चों की पहचान के अधिकार-पर चर्चा की गई। साक्ष्य अधिनियम, 1872 - s.112-का उद्देश्य-आयोजित: एक बच्चे को पितृत्व की खोज में खोया नहीं जाना चाहिए-बहुमूल्य बचपन और

युवावस्था को किसी के पितृत्व के बारे में जानने की खोज में खोया नहीं जा सकता है इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का संपूर्ण उद्देश्य जो एक वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करता है, जिसका ठोस और मजबूत साक्ष्य द्वारा खंडन किया जाना चाहिए-अवैधता के बारे में एक निष्कर्ष, यदि डीएनए परीक्षण में प्रकट होता है, तो बच्चे पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ता है।

चर्चा की। साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss. 4 , 112 - आयोजित किया गया: एस. एस. का एक संयुक्त पठन। 4 और 112 यह दिखाएगा कि एक बार पार्टी सवाल उठाएगी

एक बच्चे के जन्म की वैधता से पता चलता है कि विवाह के पक्षों की एक-दूसरे तक कोई पहुँच नहीं थी, फिर एस का लाभ था। 112 एस का आह्वान करने वाले दल के लिए उपलब्ध नहीं है। 112 - हालाँकि, यदि ऐसा पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि उसकी शादी के लिए दूसरे पक्ष तक कोई पहुँच नहीं थी, तो एस की ढाल। 112 दूसरे पक्ष की इस हद तक रक्षा करता है कि उसे किसी भी प्रमाण से छेदा नहीं जा सकता है एस में निहित निषेध। 4 .

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

शब्द और वाक्यांश:

" यह मान सकते हैं कि "," मान लेंगे "और" निर्णायक प्रमाण "पर चर्चा की गई-साक्ष्य अधिनियम, 1872-एस. एस. 4 , 112 और 114।

" अनुमान "" , प्रतिकूल अनुमान "-का अर्थ-चर्चा की गई।

मैक्सिम-पिता विवाह के प्रदर्शक थे-आयोजित: एक बच्चे की अवैधता के बारे में प्रश्न, के दावे के लिए केवल आकस्मिक हैं व्यभिचार या बेवफाई के आधार पर विवाह का विघटन

व्यभिचार को साबित करने के लिए नियमित आधार पर डी. एन. ए. परीक्षणों को आयोजित करने की अनुमति देना, उपरोक्त सिद्धांत को फिर से परिभाषित करने के बराबर होगा, जिसका अर्थ है, पिता वह है जिसे विवाहकर्ता इंगित करते हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. धारा 112 में अंतर्निहित सिद्धांत है -

उस बच्चे के पितृत्व के बारे में अनुचित पूछताछ को रोकें जिसके माता-पिता की प्रासंगिक समय पर एक-दूसरे तक "पहुंच" थी।

दूसरे शब्दों में, एक बार जब किसी विवाह को वैध माना जाता है, तो उस विवाह से पैदा हुए बच्चों के बारे में एक मजबूत धारणा है

वैध होना। इस धारणा का खंडन केवल इसके विपरीत मजबूत, स्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक नीति की धारणा पर आधारित है। चूंकि धारा 112 एक धारणा बनाती है -

वैधता कि विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है, उस व्यक्ति पर बोझ डाला जाता है जो बच्चे की वैधता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा, "पहुँच" या "गैर पहुँच" का अर्थ वास्तविक सहवास नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है

" यौन संबंधों के लिए अवसरों का अस्तित्व "या" गैर-अस्तित्व "। धारा 112 जन्म के समय को महत्वपूर्ण पहलू के रूप में संदर्भित करती है न कि गर्भधारण के समय के रूप में। गर्भधारण का समय केवल यह देखने के लिए प्रासंगिक है कि पति के पास था या नहीं। पत्नी तक पहुँच नहीं थी। इस प्रकार, विवाह के जारी रहने के दौरान जन्म वैधता का "निर्णायक प्रमाण" है जब तक कि "नहीं"

जिस समय बच्चा पैदा हो सकता था, उस समय बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाने वाले पक्ष की पहुँच द्वारा साबित किया जाता है

पार्टी ने कहा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को धारा 4 के तहत "निर्णायक प्रमाण" की परिभाषा के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बच्चा वैध [2023] 4 एस. सी. आर. के दौरान पैदा हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवाह को एक वैध संतान माना जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह दिखाया गया हो कि विवाह के पक्षकारों की किसी भी समय एक-दूसरे तक कोई पहुंच नहीं थी जब बच्चे का जन्म हो सकता था या विवाह के विघटन के 280 दिनों के भीतर और माँ अविवाहित रहती है, यह तथ्य निर्णायक प्रमाण है कि बच्चा पुरुष का वैध पुत्र है। संबंधित समय पर गैर-पहुंच साबित करके निर्णायक धारणा के संचालन से बचा जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के बाद के भाग से संकेत मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति यह स्थापित करने में सक्षम है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा पैदा हो सकता था, तो ऐसे बच्चे की वैधता से इनकार किया जा सकता है। अर्थात्, यह मजबूत और ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि गंभीर बीमारी या नपुंसकता के कारण उनके बीच पहुंच असंभव थी या उस अवधि के दौरान पक्षों के बीच यौन संबंध की कोई संभावना नहीं थी जब बच्चा पैदा हुआ होगा। इस प्रकार, जब तक पहुंच की अनुपस्थिति स्थापित नहीं होती है, वैधता की धारणा को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जहाँ पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, और कोई नपुंसकता साबित नहीं होती है, वहाँ उनके जन्म से पैदा हुआ बच्चा विवाह को निर्णायक रूप से वैध माना जाता है, भले ही पत्नी को, उसी समय, बेवफाई का दोषी दिखाया गया हो। यह तथ्य कि एक महिला व्यभिचार में रह रही है, अपने आप में एक बच्चे की वैधता के पक्ष में निर्णायक धारणा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, प्रभाव के लिए सबूत के टुकड़े

कि पति ने गर्भधारण की अवधि में पत्नी के साथ संभोग नहीं किया था, केवल विवाह में पैदा हुए बच्चे की अवैधता की ओर इशारा कर सकता है, लेकिन यह इस धारणा को उखाड़ नहीं पाएगा कि धारा 112 के तहत वैधता। धारा 112 के तहत अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब बच्चा एक वैध विवाह के जारी रहने के दौरान पैदा हुआ हो और अन्यथा नहीं। अभिगम "या" गैर-अभिगम "

यौन संभोग के संदर्भ में होना चाहिए जो यौन अर्थ में और इसलिए, उस संकीर्ण अर्थ में है। पहुँच के लिए हो सकता है

विभिन्न कारणों से नपुंसकता या अक्षमता या पति की मृत्यु के बाद से समय बीतना। इस प्रकार, भले ही पति सहवास कर रहा हो सकता है, पति और पत्नी के बीच गैर-पहुंच हो सकती है। सह-निवास के बावजूद गैर-पहुंच के उदाहरणों में से एक पति की नपुंसकता है।

यदि ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया वी. अजिंक्य अरुण फिरोदिया

पति के पास पहुँच है, पत्नी की ओर से व्यभिचार अवैधता के निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएगा। इस प्रकार, "गैर-पहुँच" को मुद्दे में एक तथ्य के रूप में साबित करना होगा और इसे एक असंदिग्ध चरित्र के प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार, सह-निवास के बावजूद पति और पत्नी के बीच "गैर-पहुँच" हो सकती है। इसके विपरीत, वास्तविक सह-निवास के अभाव में भी, वहाँ पहुँच हो सकती है। धारा 112 को ऐसे समय में लागू किया गया था जब डी. एन. ए. परीक्षणों के साथ-साथ रिबोन्यूक्लिक एसिड परीक्षण (संक्षेप में 'आर. एन. ए. ') जैसे आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण लागू नहीं थे। विधायिका का चिंतन। हालाँकि, एक वास्तविक डी. एन. ए. परीक्षण का परिणाम भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान की निर्णायकता से बच नहीं सकता है। अगर पति

गर्भधारण के समय और पत्नी एक साथ रह रहे थे, लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण से पता चलता है कि बच्चे का जन्म पति से नहीं हुआ था। जो साबित होगा, वह पत्नी की ओर से व्यभिचार है, हालाँकि, बच्चे की वैधता अभी भी कानून में निर्णायक होगी। दूसरे शब्दों में, एक वैध विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे के पितृत्व की निर्णायक धारणा यह है कि बच्चा पति का है और इसका खंडन केवल डीएनए परीक्षण रिपोर्ट से नहीं किया जा सकता है। खंडन करने के लिए जो आवश्यक है वह उस समय गैर-पहुँच का प्रमाण है जब बच्चा पैदा हो सकता था, यानी उसकी गर्भधारण के समय। [अनुच्छेद 8.1-8.7] [704-डी-जी; 705-बी-एच; 706 ए-ई]

शाम लाल बनाम संजीव कुमार (2009) 12 एस. सी. सी. 454: [2009] 5 एससीआर 1049; कामती देवी बनाम पोशी राम, (2001) 5 एससीसी 311: [2001] 3 एससीआर 729-पर निर्भर।

2.1 एक निष्कर्ष पर पहुँचने के उद्देश्य से, न्यायालय एक तथ्यात्मक अनुमान पर भरोसा कर सकता है जब तक कि अनुमान न हो

अस्वीकृत या खारिज या खंडन किया गया। हालाँकि, धारा 114 के चित्रण (एच) ने न्यायालय को तथ्यों से कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त विवेकाधीन शक्ति दी है। इस धारा के तहत अनुमान विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। उक्त प्रावधान में "अनुमान लगाया जा सकता है" वाक्यांश का उपयोग इंगित करता है कि न्याय न्यायालयों को विशेष तथ्यों के प्रभाव का न्याय करने में और यह निर्धारित करने में कि क्या उनसे कोई अनुमान लगाया जाना है, अपनी स्वयं की समझ और अनुभव का उपयोग करना है। अनुमान यह हैं कि

तथ्यों के आधार पर स्थापित, और न्यायालय को एक तथ्य का अनुमान लगाने या न लगाने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है।

3] 4 एस. सी. आर. में तथ्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दीपानविता रॉय इतने सम्मोहक थे कि डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश को उचित ठहरा सके। उक्त मामले में, पति ने गैर-पहुंच का एक विशिष्ट अनुरोध लिया था। इसके अलावा, अदालत ने स्वीकार किया कि डी. एन. ए. परीक्षण ही एकमात्र तरीका होगा जिससे व्यभिचार के मामले को साबित किया जा सकता है। उक्त मामले में डी. एन. ए. परीक्षण की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सच्चाई को स्थापित करने के लिए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता-पत्नी ने डी. एन. ए. परीक्षण के संबंध में न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया, तो उसके खिलाफ व्यभिचार के आरोपों का निर्धारण एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर किया जाएगा जैसा कि चित्रण (एच) के तहत विचार किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114। हालाँकि, उक्त मामले में किए गए इस तरह के अवलोकन को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है जो सभी मामलों में एक संकीर्ण तरीके से लागू किया जा सकता है जिसमें पत्नी डी. एन. ए. परीक्षण के संबंध में न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इनकार करती है। वर्तमान मामले के तथ्य न तो मास्टर 'एक्स' का डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश की गारंटी देते हैं, न ही वे अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत, अपने बेटे को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन करने से इनकार करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने को उचित ठहराते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, न्यायालय द्वारा प्रतिकूल या अन्यथा निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। इसलिए, दीपानविता राय में इस न्यायालय के फैसले को उपरोक्त संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। तत्काल मामले में, मास्टर 'एक्स' के पितृत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है क्योंकि बहस के दौरान भी यह स्वीकार किया गया था कि मास्टर 'एक्स' का जन्म पक्षों के निरंतर सहवास के दौरान हुआ था और इस प्रकार एक वैध विवाह के निर्वाह के दौरान हुआ था। मास्टर 'एक्स' के पितृत्व का मुद्दा इसमें अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार के मुद्दे से अलग है। मास्टर 'एक्स' का इसमें पक्षकारों का एक वैध बच्चा होने के नाते अपीलार्थी की ओर से कथित व्यभिचार से कोई लेना-देना नहीं है। अतः दीपानविता राय में इस न्यायालय का निर्णय प्रत्यर्थी के लिए कोई सहायक नहीं है।

यहाँ। [पैरा 9.2,10.1] [707-एफ-एच; 710-एच; 711-ए; 710-एफ-जी; 711 बी, ई-एफ, एच; 712-ए]

दीपानविता रॉय बनाम रोनोब्रोतो रॉय, (2015) 1 एस. सी. सी. 365:

[2014] 11 एससीआर 553-प्रतिष्ठित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 9 वां संस्करण-संदर्भित।

2.2 निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार किया जा सकता है -

जिन परिस्थितियों में नाबालिग बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण करने का निर्देश दिया जा सकता है: आई. कि एक नाबालिग बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्या फिरोडिया बी. है।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

विवाद। पक्षकारों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे पितृत्व के तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करें और केवल तभी जब न्यायालय इस तरह के साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना असंभव लगता है, या मुद्दे में विवाद को डी. एन. ए. परीक्षण के बिना हल नहीं किया जा सकता है, यह डी. एन. ए. परीक्षण को निर्देशित कर सकता है और अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, केवल असाधारण और योग्य मामलों में, जहां इस तरह का परीक्षण विवाद को हल करने के लिए अपरिहार्य हो जाता है, न्यायालय इस तरह के परीक्षण का निर्देश दे सकता है। वी. साबित करने के साधन के रूप में डी. एन. ए. परीक्षणों का निर्देशन करते हुए

व्यभिचार, न्यायालय को व्यभिचार से पैदा हुए बच्चों पर उसके परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए, जिसमें विरासत से संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक आदि शामिल हैं। [पैरा 12] [716-डी-एच; 717-ए-सी] 3. बच्चों को यह अधिकार है कि अदालत के समक्ष उनकी वैधता पर तुच्छ सवाल न उठाए जाएं। यह जरूरी है

निजता के अधिकार की विशेषता। इसलिए अदालतों को यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बच्चों को भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं माना जाना चाहिए, और उन्हें फोरेंसिक/डीएनए परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब वे तलाक की कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं। [पैरा 17] [718-एच; 719-ए]

4. एक बच्चे के लिए गोपनीयता की अवधारणा एक वयस्क के बराबर नहीं हो सकती है। हालांकि, बच्चों की विकसित क्षमता मान्यता दी गई है और कन्वेंशन इस नियंत्रण को स्वीकार करता है कि बच्चों सहित व्यक्तियों का अपनी व्यक्तिगत सीमाओं और उन साधनों पर नियंत्रण है जिनके द्वारा वे परिभाषित करते हैं कि कौन [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वे अन्य लोगों के संबंध में हैं। बच्चों को प्रभावित करने और उन्हें समझने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

केवल बच्चे होने के कारण स्वयं की भावना। [पैरा 21] [720-डी]

5. एक माता-पिता, बच्चे के सर्वोत्तम हित में, चुन सकते हैं

बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण न कराना। यह भी गोपनीयता के अधिकार के मूल सिद्धांतों के विपरीत है कि किसी व्यक्ति से ऐसा करने की आवश्यकता है खुलासा करें, रेम में कार्यवाही के दौरान, चिकित्सा

गर्भधारण के लिए प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया। माता-पिता के इनकार करने के कई कारण हो सकते हैं, और इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना विवेकपूर्ण नहीं है, हर उस मामले में जहां माता-पिता बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने से इनकार करते हैं। [पैरा 22.3] [723-डी-ई]

6. एक बच्चे की अवैधता के बारे में प्रश्न, केवल व्यभिचार के आधार पर विवाह के विघटन के दावे के लिए आकस्मिक हैं।

या बेवफाई। व्यभिचार को साबित करने के लिए, नियमित आधार पर डी. एन. ए. परीक्षणों को आयोजित करने की अनुमति देना, इस उक्ति को फिर से परिभाषित करने के बराबर होगा, जिसका अर्थ है, पिता वह है जिसे विवाहकर्ता इंगित करते हैं। व्यभिचार और बेवफाई के आरोपों से निपटने के दौरान, बच्चे के डीएनए परीक्षण का अनुरोध, न केवल धारा 112 के तहत धारणा के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, बल्कि शारीरिक स्वायत्तता की अनिवार्यता के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है। [पैरा

24] [724 - बी-सी]

दुखतर जहां बनाम मोहम्मद फारूक (1987) 1 एस. सी. सी.

624 : [1987] 1 एस. सी. आर. 1086-- पर निर्भर था।

7. प्रत्यर्थी-पति का मामला यह है कि यदि डीएनए परीक्षण की अनुमति दी जाती है और उसी से पता चलता है कि वह जैविक नहीं है

'एक्स' के पिता, एक परिणाम के रूप में, यह साबित होगा कि अपीलार्थी पत्नी ने व्यभिचार किया था। यह न्यायालय इसके पक्ष में नहीं है

निम्नलिखित कारणों से व्यभिचार साबित करने के लिए प्रतिवादी-पति द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण: आई. यह विवाद में नहीं है कि मास्टर 'एक्स', बेटा जिसे अपीलार्थी से पैदा हुआ बताया गया है-विवाह से पत्नी, वर्ष 2013 में पैदा हुआ था। डी. एन. ए. परीक्षण, का उपयोग एक दशक पहले या बाद में मास्टर 'एक्स' के जन्म के बाद हुई बेवफाई को स्थापित करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता है।

ii. वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, डी. एन. ए. परीक्षण एकमात्र तरीका नहीं होगा जिसमें मामले की सच्चाई ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्या फिरुडिया बनाम हो सकती है।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

स्थापित किया गया। प्रत्यर्थी-पति ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग/प्रतिलेख और अपीलार्थी की दैनिक डायरी है, जिसे अपीलार्थी की बेवफाई साबित करने के लिए कानून के अनुसार बुलाया जा सकता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ऐसे साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार/बेवफाई का मामला बनाने का प्रयास करने की स्थिति में है। iii. प्रत्यर्थी-पति द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को हटाने के लिए गैर-पहुंच के रूप में कोई याचिका नहीं उठाई गई है।

इसलिए, प्रतिवादी द्वारा कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है जो मास्टर 'एक्स' का डीएनए परीक्षण करने के निर्देश को उचित ठहराए। iv. मास्टर 'एक्स' की वैधता या पितृत्व के संबंध में तत्काल मामले में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं उठाया जा सकता है, जिसमें मास्टर 'एक्स' को पितृत्व परीक्षण के लिए विषय बनाने से इनकार करने पर अपीलार्थी की वैधता या पितृत्व के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा विषय से इनकार करने पर पितृत्व परीक्षण के लिए मास्टर 'एक्स', अपीलार्थी की ओर से कथित व्यभिचार के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। व्यभिचार के आरोप को यहाँ प्रत्यर्थी द्वारा मास्टर 'एक्स' के पितृत्व के मुद्दे को साबित करना होगा। [पैरा 26] [724-एफ-एच; 725-ए-डी]

नंदलाल वासुदेव बदवैक बनाम लता नंदलाल बदवैक,

(2014) 2 एससीसी 576: [2014] 1 एससीआर 120-विशिष्टा
शारदा बनाम धर्मपाल (2003) 4 एस. सी. सी. 493: [2003] 3

एस. सी. आर. 106; गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,

(1993) 3 एससीसी 418: [1993] 3 एस. सी. आर. 917; गौतम कुंडू, भवानी
प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव, उड़ीसा

राज्य महिला आयोग (2010) 8 एस. सी. सी. 633: [2010]

9 एससीआर 457; इनायत अली बनाम तेलंगाना राज्य, एम. ए. एन. यू /

एससी/1538/2022; अशोक कुमार बनाम राज गुप्ता, (2022) 1

एस. सी. सी. 20 - पर भरोसा किया।

एलआरएस द्वारा पेरुमल नादर (मृत)। बनाम पोन्नूस्वामी, (1970)

1 एससीसी 605: [1971] 1 एस. सी. आर. 49; उदय चंद दत्त बनाम

सभी ई. आर. 1023-संदर्भित।

साक्ष्य के कानून पर सरकार, 20 वां संस्करण; रेडन और

जैक्सन ऑन डिवोर्स एंड फैमिली मैटर्स (1983) वॉल्यूम। में,

पीजी में। 1054 संदर्भित किया गया।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर बी. रामसुब्रमणियन, जे. (सहमत)

1.1 एक ऐसी स्थिति से निपटने के दौरान जहां धारा 114 के तहत चित्रण (एच) के संदर्भ में एक अनुमान उठाया जाना चाहिए, न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या व्यक्ति ने ऐसा करने से इनकार किया है।

उत्तर, इस डर के कारण है कि उत्तर मुद्दे में मामले के संबंध में उसके लिए प्रतिकूल परिणाम पैदा कर सकता है या इस डर के कारण है कि इस तरह के उत्तर से उसे किसी ऐसे मामले में नुकसान हो सकता है जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। धारा 112 किसी ऐसी चीज से संबंधित है जिसमें किसी तथ्य के अस्तित्व को निर्णायक प्रमाण माना जाता है, जिसमें विवाद करने वाले पक्ष के लिए साक्ष्य देने की कोई संभावना नहीं होती है।

उसी को अस्वीकार करना। धारा 112 के लाभ से किसी अन्य व्यक्ति को वंचित करने के लिए एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र मार्ग यह दिखाना है कि विवाह के पक्षों की उस समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा पैदा हो सकता था। धारा 114 का न तो कोई लेना-देना है और न ही इसका संबंध धारा 112 द्वारा व्यवहार की गई वैधता के निर्णायक प्रमाण से है। धारा 112 और धारा 114 दोनों अलग-अलग विभागों के अंतर्गत आती हैं। वह शब्द।

" धारा 112 में स्वयं अनुमान का उपयोग नहीं किया गया है। धारा 112 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निर्णायक प्रमाण" है। इसलिए, धारा 4 के आधार पर, इस उद्देश्य के लिए कोई साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसे अस्वीकार करने के लिए। यदि विवाह के पक्षों में से एक यह दर्शाता है कि उस समय उसकी दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा कर सकता था

1.2 हाथ में मामले में, परिवार न्यायालय के समक्ष तलाक के लिए अपनी याचिका में प्रतिवादी का निवेदन यह है कि दूसरा बच्चा-मास्टर 'एक्स' का जन्म 17.7.2013 पर हुआ था और प्रतिवादी को इसमें अपीलार्थी के कथित व्यभिचारी व्यवहार के बारे में केवल 14.9.2016 पर पता चला था। प्रत्यर्थी की इस प्रभाव की अभिवचन कि सितंबर 2016 के बाद, अपीलकर्ता-पत्नी के साथ उसका कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा है, इसका मतलब है कि कम से कम उस समय तक जब बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद भी तीन साल की पूरी अवधि के लिए उसकी पत्नी तक पहुंच थी। इसलिए, धारा 112 के तहत निर्णायक सबूत वास्तव में इस मामले में काम में आया है। [पारस 24,25] [735-एफ; 736-ए-बी] अपर्णा अजिंक्य फिरुडिया बनाम।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

1.3 जिस स्तर पर पत्नी बच्चे को डी. एन. ए. के अधीन करने से इनकार कर सकती है, वह अदालत के आने के बाद ही उत्पन्न होगी

निष्कर्ष है कि एक डीएनए परीक्षण का आदेश दिया जाना चाहिए। [पैरा 26] [736-सी]

1.4 एक प्रतिकूल निष्कर्ष, कानून में, केवल उस व्यक्ति के खिलाफ निकाला जा सकता है जो किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है। हाथ पर मामले में,

अपीलार्थी की दोहरी भूमिका है, अर्थात्, प्रत्यर्थी की पत्नी की और मास्टर एक्स की माँ की। यदि अपीलार्थी कुछ करता है या करने से इनकार करता है, तो एक प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं के लिए लाभप्रद, उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन एक माँ और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में उसकी क्षमता में यदि अपीलार्थी बच्चे के हितों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण करने से इनकार करती है, तो उसके खिलाफ व्यभिचार का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने से इनकार करके, वह वास्तव में बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा कर रही है। के लिए

बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करते हुए, अपीलार्थी-पत्नी को पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन प्रतिकूल निष्कर्ष के साथ दंडित नहीं किया जा सकता है। धारा 114 (एच) का सहारा लेकर, प्रतिवादी अपीलार्थी को पकड़-22 की स्थिति में नहीं डाल सकता है। इसलिए, धारा 114 (एच) का उस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां एक माँ मामले दर्ज करने से इनकार करती है।

बच्चे का डीएनए परीक्षण किया जाता है। मुख्य उत्पाद के रूप में डी. एन. ए. परीक्षण से जो निकलता है, वह बच्चे का पितृत्व है, जिसे परीक्षण के अधीन किया जाता है। संयोग से, पत्नी का व्यभिचारी आचरण भी उसी प्रक्रिया के माध्यम से एक उप-उत्पाद के रूप में स्थापित होता है। धारा 114 में केवल "मे" शब्द का उपयोग किया गया है न कि "विल" शब्द का। इसलिए, प्रदर्शनी में व्यक्त बाधाओं को

धारा 114 के तहत चित्रण (एच) न्यायालय को बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाने के लिए मना कर सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी का यह तर्क कि जिसे लागू करने की मांग की गई है, केवल धारा 114 (एच) है और धारा 112 नहीं है, खारिज कर दिया जाता है। [पारस 28-32] [736-F-H; 737-A-E]

2. सवाल यह है कि क्या डीएनए परीक्षण किया जाना चाहिए

बच्चे पर अनुमति, बच्चे के चश्मे के माध्यम से विश्लेषण किया जाना है न कि माता-पिता के चश्मे के माध्यम से। बच्चे को मोहरे के रूप में यह दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि बच्चे की मां व्यभिचार में रह रही थी। प्रत्यर्थी पति के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह अन्य साक्ष्यों से पत्नी के व्यभिचारी आचरण को साबित करे, लेकिन बच्चे के पहचान के अधिकार का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। [पैरा 33] [737-एफ-जी] [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दीपानविता रॉय बनाम रोनोब्रोतो रॉय (2015) 1 एस. सी. सी. 365:

[2014] 11 एससीआर 553; शारदा बनाम धर्मपाल (2003) 4

एससीसी 493: [2003] 3 एस. सी. आर. 106; सहारा इंडिया रियल एस्टेट

निगम लिमिटेड और अन्य। बनाम प्रतिभूति और विनिमय

भारतीय बोर्ड और ए. एन. आर. (2012) 10 एससीसी 603: [2012] 12

एस. सी. आर. 256-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 1 एससीआर 120

प्रतिष्ठित

रा

4.5

पै
(iii)

पैरा 4.7 (ii)

[2003] 3 एससीआर 106

उस पर भरोसा करें

[1993] 3 एससीआर 917

उस पर भरोसा करें

रा 6

पै

[2010] 9 एससीआर 457

उस पर भरोसा करें

रा 6.2

पै

[1971] 1 एससीआर 49

संदर्भित किया गया है

रा 6.2

[2014] 11 एससीआर 553

प्रतिष्ठित

पै

रा 7.4

[2009] 5 एससीआर 1049

पै

रा 8.1

[2001] 3 एससीआर 729

उस पर भरोसा करें

पै

उस पर भरोसा करें

रा 8.7

[1987] 1 एससीआर 1086

पै

उस पर भरोसा करें

रा 23

बी के निर्णय में।

पै

रामसुब्रमण्यन, जे।

[2014] 11 एससीआर 553

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2003] 3 एससीआर 106

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

रा 34

संदर्भित किया गया है

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.1308

2023 तक।

उच्च न्यायालय के 22.11.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के सी. डब्ल्यू. पी. No.7077 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सन्यात लोढ़ा, सुश्री आकाशी लोढ़ा,

रवि रघुनाथ, संजना, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रोहन राजदाक्ष, सुश्री पर्सिस अंकलेश्वरी,

श्लोक चंद्र, विक्रान्त पचनंदा, सुश्री अपराजित जामवाल, ऋषभ पारिख, अनुपम संभस, सुश्री
अरुणिमा कुमारी, मुकुल कत्याल, केशव गर्ग, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

नागरत्ना, जे.

छुट्टी दे दी गई।

बच्चे को औपचारिक रूप से गोद लेने के माध्यम से माता-पिता बनना। भारतीय कानूनी स्पेक्ट्रम के तहत, एक पति को अपनी पत्नी से पैदा हुए बच्चे का पिता माना जाता है। इस प्रकार, के बारे में एक मजबूत धारणा है एक बच्चे का पितृत्व। इस धारणा को केवल पति की किसी भी प्रजनन भूमिका को रोकने वाले साक्ष्य से दूर किया जा सकता है, जैसे कि यह दिखाना कि संभावित गर्भधारण के प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी की एक-दूसरे तक कोई पहुंच नहीं थी। गैर-पहुंच के प्रमाण के अभाव में, कानून पति के पितृत्व को निर्णायक रूप से स्थापित मानता है यदि वे उस समय सहवास करते थे जब बच्चे के गर्भ धारण करने की संभावना थी। सबूत के साथ खंडन की अनुमति देकर, कि पति जैविक पिता नहीं हो सकता था, वैवाहिक धारणा निहित रूप से, आंशिक रूप से, एक

माता-पिता को जैविक प्रजनन से जोड़ने और पति के आनुवंशिक योगदान की संभावना के बारे में एक धारणा पर नीति। यह धारणा जैविक माता-पिता की तुलना में सामाजिक माता-पिता की रक्षा करती है। वैज्ञानिक प्रमाण अब आभासी निश्चितता के साथ यह जानना संभव बनाता है कि क्या एक आदमी आनुवंशिक रूप से एक बच्चे से संबंधित है। नतीजतन, अदालतों का नियमित रूप से उन पतियों के साथ सामना किया जाता है जो नए प्राप्त डीएनए साक्ष्य के आधार पर अपने पितृत्व को अस्वीकार करने की मांग करते हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने लंबे समय तक एक बच्चे के लिए पिता की सामाजिक भूमिका निभाई है। वर्तमान अपील में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि एक न्यायालय पितृत्व को विवाह से जोड़ने वाली कानून की सुव्यवस्थित धारणाओं को कैसे रोक सकता है, विशेष रूप से जब पक्ष नियमित रूप से आधुनिक आनुवंशिक प्रोफाइलिंग तकनीकों को नियोजित करके ऐसी धारणाओं को हटाने का प्रयास कर रहे हैं।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

3. वर्तमान विवाद प्रत्यर्थी-पति द्वारा 9 नवंबर, 2020 को प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पुणे के समक्ष दायर एक आवेदन (प्रदर्शनी 84/बी) से सामने आता है, जिसमें अपीलकर्ता-पत्नी से पैदा हुए दूसरे बच्चे मास्टर "एक्स" को प्रत्यर्थी के साथ उसकी शादी के निर्वाह के दौरान डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक के अधीन करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की गई थी। उसके पितृत्व का पता लगाने के उद्देश्य से एसिड परीक्षण (संक्षेप में "डीएनए परीक्षण")। उक्त आवेदन प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू [2023] 4 एस. सी. आर. की धारा 13 (1) (आई) और (आई. ए.) के तहत दायर तलाक की याचिका में दायर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवाह अधिनियम, 1955, याचिका सं। 2017 का पी. ए. 639। इसे परिवार न्यायालय, पुणे द्वारा 12 अगस्त, 2021 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 22 नवंबर, 2021 के सिविल रिट याचिका No.7077 में विवादित फैसले के माध्यम से पुष्टि की गई थी।

4. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान अपील के लिए अग्रणी तथ्य इस प्रकार हैं

निम्नलिखित है:

4.1 . अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने 23 नवंबर, 2005 को पुणे में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार शादी की। उनके पहले बच्चे, मास्टर "वाई" का जन्म 21 दिसंबर, 2009 को हुआ था। उनकी शादी के निर्वाह के दौरान, एक दूसरे बेटे, मास्टर "एक्स" का जन्म 17 जुलाई, 2013 को हुआ था।

4.2 . 1 जून, 2017 को प्रतिवादी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) और (ia) के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की।

1955 2017 की याचिका No.P.A. 639 और परिवार न्यायालय, पुणे के समक्ष अपीलार्थी पत्नी के खिलाफ 2017 की पी. डी. संख्या 17 के रूप में उनके दो बच्चों की अभिरक्षा की मांग करने वाली याचिका है। तलाक की याचिका में, प्रतिवादी ने, अन्य बातों के साथ, आरोप लगाया कि अपीलार्थी-पत्नी क्षितिज बाफना और प्रतिवादी के साथ व्यभिचार संबंध में थी। 14 सितंबर, 2016 को उन्हें इसका पता चला जब उन्होंने पाया कि अपीलार्थी और क्षितिज बाफना के बीच कुछ अंतरंग संदेशों का आदान-प्रदान किया गया था।

4.3 . 9 नवंबर, 2020 को, प्रत्यर्थी ने परिवार न्यायालय, पुणे के समक्ष आवेदन 84/बी के रूप में एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलार्थी-पत्नी से पैदा हुए दूसरे बच्चे मास्टर "एक्स" को डीएनए परीक्षण के लिए प्रत्यर्थी के साथ उसकी शादी के निर्वाह के दौरान विषय बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।

बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए। उक्त आवेदन की सामग्री को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

वह स्वामी "एक्स", अपीलार्थी से पैदा हुआ दूसरा पुत्र

आई.

पत्नी, प्रतिवादी के साथ अपनी शादी के निर्वाह के दौरान, अपीलार्थी और क्षितिज बाफना के बीच एक व्यभिचारी संबंध से पैदा हुई थी।

कि प्रत्यर्थी को पता चला कि अपीलार्थी था

ii.

क्षितिज बाफना के साथ एक व्यभिचारी संबंध में, जब वह 14 सितंबर, 2016 को उसके फोन का उपयोग कर रहा था। कि उसी के बारे में सामना किए जाने पर अपीलार्थी ने स्वीकार किया

क्षितिज बाफना के साथ व्यभिचारी संबंध।

A AJINKYA FIRODIA v. अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

कि प्रत्यर्थी, अपीलार्थी द्वारा पुष्टि की गई सच्चाई को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होने के कारण, मास्टर "एक्स" के पितृत्व के मुद्दे की जांच करने का फैसला किया और इसलिए, एक निजी प्रयोगशाला, डी. एन. ए. लैब्स इंडिया में डी. एन. ए. परीक्षण किया गया। 24 नवंबर, 2016 की डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट ने निम्नानुसार संकेत दिया:

" कथित पिता में आनुवंशिक मार्करों की कमी होती है जिन्हें जैविक पिता द्वारा बच्चे को दिया जाना चाहिए। द.

पितृत्व की संभावना 0 प्रतिशत है।

कि प्रत्यर्थी निश्चित था कि मास्टर "एक्स" का जन्म अपीलार्थी के व्यभिचारी संबंध के परिणामस्वरूप हुआ था।

हालाँकि, अपने तर्क को साबित करने के लिए

तलाक के आधार के रूप में अपीलार्थी की बेवफाई, यह थी

एक डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए आवश्यक है जिससे पता चलता है कि उत्तरदाता मास्टर "एक्स" का जैविक पिता नहीं था।

अपीलार्थी की ओर से बेवफाई का दावा। कि इसकी अनुपस्थिति में यह असंभव होगा किए गए दावों को निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए प्रतिवादी

दलीलों में उसके द्वारा।

अर्थात्, श्री बाफना की पत्नी, अपीलार्थी के साथ उसके अवैध संबंधों के बारे में। क्षितिज बाफना जब मास्टर "एक्स" के पितृत्व के बारे में सामने आए, तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि बच्चे का जन्म उनके और अपीलार्थी से हुआ था। कि अपीलार्थी में था एक दैनिक डायरी रखने की आदत जिसमें उसने अपने व्यभिचारी संबंध के बारे में अपने विचार लिखे थे। बातचीत की संवेदनशील प्रकृति और डायरी की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी ने परिवार की अनुमति मांगी

अभिलेख, डायरी और अन्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय साक्ष्य, यदि आवश्यक हो, अंतिम सुनवाई के समय

तलाक की कार्यवाही।

अपीलार्थी ने जवाब में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें मास्टर [2023] 4 एस. सी. आर. का डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश की मांग करने वाले आवेदन प्रतिवादी का विरोध किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"एक्स", अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए कि प्रतिवादी ने प्रथम दृष्टया ऐसा मामला नहीं बनाया था जिसमें न्यायालय को डी. एन. ए. को निर्देशित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता थी।

प्रार्थना के अनुसार परीक्षण किया जाना।

4.5 . 12 अगस्त, 2021 के एक आदेश द्वारा, परिवार न्यायालय, पुणे ने प्रतिवादी द्वारा डीएनए परीक्षण की मांग करने वाले आवेदन को मंजूरी दे दी।

मास्टर "एक्स" और आगे कहा कि यदि अपीलकर्ता न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ व्यभिचार के आरोपों का निर्धारण एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर किया जाएगा:

भारतीय साक्ष्य की धारा 114 के चित्रण (एच) के तहत विचार किया गया

अधिनियम, 1872 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "साक्ष्य अधिनियम")। परिवार न्यायालय के मुख्य निष्कर्षों को निम्नानुसार संकलित किया जा सकता है:

आई.

कि प्रतिवादी ने निर्देश की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था

मास्टर "एक्स" का डी. एन. ए. परीक्षण करना, केवल अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार स्थापित करने और नाबालिग बच्चे के पितृत्व का अपमान नहीं करने की दृष्टि से।

ii.

डीएनए लैब्स द्वारा जारी डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन पर

भारत दिनांक 24 नवंबर, 2016 को, परिवार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी के जैविक पिता मास्टर "एक्स" होने की संभावना को बाहर रखा गया है। परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 14 का वह दृष्टिकोण -

रिपोर्ट को सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है।

नंदलाल में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था।

iii.

वासुदेव बदवैक बनाम लता नंदलाल बदवैक, (2014) 2 एस. सी. सी. 576 ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को ऐसे समय में अधिनियमित किया गया था जब डी. एन. ए. परीक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति उतनी परिष्कृत नहीं थी। हालांकि धारा 112 में गणना की गई शर्तों की संतुष्टि पर निर्णायक प्रमाण का अनुमान लगाया गया है, जिसका खंडन किया जा सकता है। कि जहाँ किसी तथ्य की सच्चाई ज्ञात होती है, वहाँ किसी भी अनुमान की कोई

आवश्यकता या जगह नहीं होती है। इस प्रकार, जब परिकल्पना किए गए निर्णायक प्रमाण के बीच टकराव होता है

कानून के तहत और वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित एक प्रमाण जिसे विश्व समुदाय द्वारा सही माना जाता है, बाद वाला

पहले वाले पर हावी होना चाहिए।

कि प्रतिवादी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया था

iv.

न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराते हुए

रक्त के नमूने एकत्र करके प्रत्यक्ष रूप से डीएनए परीक्षण करना

प्रतिवादी और नाबालिग बच्चा।

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरुदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

कि प्रत्यर्थी अपनी पुष्टि करने में सक्षम होगा

वी.

अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार/बेवफाई के आरोप, केवल तभी जब डी. एन. ए. परीक्षण करने की अनुमति दी जाती है।

कि प्रतिवादी के लिए डीएनए परीक्षण के अलावा अभिवचनों में किए गए दावों को स्थापित और पुष्टि करना असंभव होगा। कि डीएनए परीक्षण सबसे अधिक है

वैध और वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण साधन, जिनका उपयोग पति अपनी बेवफाई के दावे को स्थापित करने के लिए कर सकता है। कि यदि अपीलार्थी निर्देश स्वीकार करता है

vi.

अदालत द्वारा जारी, डीएनए परीक्षण निर्धारित करेगा निर्णायक रूप से लगाए गए आरोपों की सत्यता

उसके खिलाफ प्रतिवादी। यदि वह न्यायालय द्वारा जारी निर्देश का पालन करने से इनकार करती है, तो आरोप का निर्धारण न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में अनुध्यात प्रकृति का अनुमान लगाकर किया जाएगा, विशेष रूप से, उसके चित्रण (एच) के संदर्भ में।

कि उपरोक्त पाठ्यक्रम को अपनाने से, बेवफाई का मुद्दा

vii.

भारतीय संविधान की धारा 112 के तहत विचार की गई धारणा को स्पष्ट रूप से बाधित किए बिना, केवल इसका निर्धारण किया जाएगा।

साक्ष्य अधिनियम।

4.6 . परिवार न्यायालय, पुणे द्वारा 12 अगस्त, 2021 को पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने दीवानी होने के नाते एक रिट याचिका दायर की।

2021 की रिट याचिका No.7707, उच्च न्यायालय के समक्ष

बॉम्बे ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर आरोप लगाया कि परिवार न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग को निर्देशित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और डी. एन. ए. परीक्षण के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, का आदेश

पारिवारिक न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई धारणा के विपरीत था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत था।

4.7 . 22 नवंबर, 2021 के विवादित फैसले से उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और

12 अगस्त, 2021 के परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निष्कर्षों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

कि प्रतिवादी ने मास्टर का डीएनए परीक्षण किया था

आई.

" डी. एन. ए. लैब्स इंडिया में एक्स. ने [2023] 4 एस. सी. आर. की रिपोर्ट तैयार की थी।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

उसी दिनांक 24 नवंबर, 2016 में उत्तरदाता के मास्टर "एक्स" के जैविक पिता होने की संभावना 0 प्रतिशत बताई गई थी। इस प्रकार, डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश के लिए एक आवेदन को आगे बढ़ाने का सहारा लेने की नींव प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से निर्धारित की गई थी।

इस सवाल के संबंध में कि क्या अपीलार्थी के नाबालिग बच्चे के डीएनए परीक्षण का निर्देश देने वाला आदेश अपीलार्थी के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगा, उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार हमेशा निम्नलिखित के अधीन हैं -

बनाम धर्मपाल, (2003) 4 एस. सी. सी. 493 उस वैवाहिक स्थिति को धारण करने के लिए अदालत के पास किसी व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का निर्देश देने की शक्ति है और इस तरह का निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 वैधता के निर्णायक प्रमाण के अनुमान का प्रावधान करती है। हालाँकि, इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है। इस तरह की धारणा का खंडन करने का एक तरीका प्रत्यर्थी द्वारा प्रदर्शित मामले की तरह एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना और स्थापित करना है।

कि एक न्यायालय को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है कि लेकिन चिकित्सा/डीएनए परीक्षण के लिए, यह असंभव होगा

अभिवचनों में किए गए दावों को स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी।
रूप से संवेदनशील था

कि परिवार न्यायालय में पर्याप्त

प्रत्यर्थी के इस कथन पर ध्यान देना कि वह मास्टर "एक्स" को अस्वीकार नहीं करेगा, भले ही पितृत्व हो। परीक्षण यह स्थापित करता है कि वह जैविक पिता नहीं है। कि प्रतिवादी ने उक्त बच्चे की अभिरक्षा के लिए भी प्रार्थना की थी, इसलिए, डीएनए परीक्षण की अनुमति देने में बच्चे के हित को खतरे में नहीं डाला गया था।

कि यदि अपीलार्थी परिवार न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ज) के तहत विचार की गई प्रकृति का अनुमान लगा सकता है।

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

4.8 . 12 अगस्त, 2021 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश के साथ-साथ विवादित फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने

वर्तमान अपील में भी ऐसा ही है।

प्रस्तुतियाँ:

5. हमने अपीलार्थी-पत्नी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हुज़ेफा अहमदी और प्रतिवादी-पति की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री कपिल सिब्बल को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। 6. शुरुआत में, श्री हुज़ेफा अहमदी ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के छोटे बेटे का डीएनए परीक्षण करने के लिए परिवार न्यायालय, पुणे के निर्देश को बरकरार रखते हुए गलती की थी। कि प्रत्यर्थी गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1993) 3 एस. सी. सी. 418 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित "प्रमुख आवश्यकता" की कसौटी को पूरा करने में विफल रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय कानून वैधता की ओर झुकता है और डी. एन. ए. परीक्षण के लिए निर्देश केवल पक्षकारों के हितों को संतुलित करने के बाद पारित किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चे के अधिकार भी शामिल हैं, और यदि इस तरह के परीक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा था कि डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश से बचा नहीं जा सकता था, और इसलिए, उसी के संचालन का निर्देश था

गलत है।

6.1 . अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए गलती की कि प्रतिवादी के इस बयान पर भरोसा करने से बच्चे का हित खतरे में नहीं पड़ेगा कि वह अपने बेटे को अस्वीकार नहीं करेगा। कि भले ही इस तरह के बयान को उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए, लेकिन यह बच्चे को उसके जन्म की अवैधता (यदि कोई हो) से जुड़े सामाजिक नतीजों से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और यह कि डी. एन. ए. परीक्षण करने का कोई भी निर्देश बच्चे के हितों के विपरीत होगा और प्रतिवादी द्वारा बच्चे के हित पर विचार किए बिना अकेले अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए इसकी मांग की जा रही है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि वैधता की ओर झुकने वाले भारतीय कानून के पीछे तर्क यह है कि डी. एन. ए. परीक्षण बच्चे की निजता के अधिकार को बाधित करेगा और वैधता के रूप में किसी भी मुद्दे का निर्दोष बच्चे पर बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, बच्चे और प्रतिवादी के हितों को संतुलित करना बच्चे के डीएनए परीक्षण के संचालन के लिए निर्देश पारित करने को उचित नहीं ठहराता है। 6.2 . श्री हुज़ेफा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी गैर-साबित करने वाले किसी भी मामले को स्थापित करने में विफल रहा है

प्रासंगिक समय पर पहुंच, ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को हटाया जा सके और इस प्रकार, कोई निर्देश [2023] 4 एस. सी. आर. नहीं हो सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चे का डीएनए परीक्षण करने के लिए पारित किया गया। कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 की भाषा और गौतम में इस न्यायालय के निर्णय कुंडू, भवानी प्रसाद जेना बनाम. संयोजक सचिव, उड़ीसा राज्य महिला आयोग, (2010) 8 एस. सी. सी. 633 और अशोक कुमार बनाम।

राज गुप्ता, (2022) 1 एस. सी. सी. 20, यह स्थापित करेगा कि डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए निर्देश की मांग करने वाले पक्ष को रिकॉर्ड पर मजबूत प्राथमिक लाने की आवश्यकता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान के खिलाफ गैर-पहुंच का प्रत्यक्ष साक्ष्य। गैर का वह स्पष्ट और संतोषजनक प्रमाण

धारा 112 के तहत धारणा का खंडन करने के लिए पहुंच की आवश्यकता है

साक्ष्य अधिनियम, एल. आर. एस. द्वारा पेरूमल नादर (मृत) द्वारा। बनाम पोन्नुस्वामी, (1970) 1 एस. सी. सी. 605। 6.3 . तत्काल मामले में, मास्टर "एक्स" का जन्म 17 जुलाई, 2013 को दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक संबंधों के जारी रहने के दौरान हुआ था।

और कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी तक पहुँच से इनकार नहीं करता है

प्रासंगिक समय।

6.4 . कि डीएनए परीक्षण करने का निर्देश पारित नहीं किया जा सकता है

अस्पष्ट सामग्री पर आधारित। कि प्रतिवादी ने 24 नवंबर, 2016 की डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा करने की मांग की है। हालांकि, उक्त डी. एन. ए. रिपोर्ट की प्रामाणिकता परीक्षण के दौरान स्थापित की जानी चाहिए और इसकी प्रामाणिकता साबित होने से पहले उस पर कोई भी निर्भरता, भविष्य में, एक पक्ष (जैसे कि प्रतिवादी) को लाइसेंस देने के बराबर होगी, जो डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए एक निर्देश की मांग कर रहा है।

6.5 . प्रत्यर्थी के इस दावे के संबंध में कि उसे सितंबर 2016 के महीने में याचिकाकर्ता के फोन पर संदेश मिले थे, जिसमें अपीलार्थी के व्यभिचारी कार्यों का खुलासा किया गया था, अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील के समर्थन में कोई सबूत या सामग्री नहीं है। वही प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार, उस पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

6.6 . कि यह कहना गलत होगा कि केवल इसलिए कि डी. एन. ए. परीक्षण वैज्ञानिक रूप से सटीक हैं, उन्हें नियमित रूप से किया जा सकता है

साक्ष्य की धारा 112 के तहत वैधता की धारणा को हटा दें।

एक्ट करें।

6.7 . यह माना गया कि वैधता का मुद्दा अटूट है

व्यभिचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है और केवल प्रतिवादी के अनुरोध पर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, वैधता की धारणा को न्यायालयों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हुज़ेफा अहमदी ने प्रार्थना की है कि तत्काल अपील की अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के साथ-साथ 12 अगस्त 2021 के परिवार न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए। 7. इसके विपरीत, प्रतिवादी-पति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि

उच्च न्यायालय का निर्णय और 12 अगस्त 2021 का परिवार न्यायालय का आदेश मामले के तथ्यों के साथ-साथ प्रासंगिक कानून की निर्विवाद सराहना पर पारित किया गया है, और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7.1 . श्री कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि तत्काल अपील कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न तो कानून के आधार पर और न ही कानून के आधार पर।

7.2 . उदय चंद दत्त बनाम सैबल सेन, (1987) पूरक एस. सी. सी. 506 में इस न्यायालय के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए कि परिवार न्यायालय और उच्च न्यायालय के दो समवर्ती निष्कर्षों के सामने, इस तरह के निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 7.3 . प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 का उल्लेख किया और कहा कि

वैवाहिक कार्यवाही एक निर्णय है और इसलिए, लंबित तलाक याचिका में एक न्यायसंगत और उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए, कोई भी

सच्चाई को सामने लाने के लिए साक्ष्य मामले के लिए सटीक है और इसे अंदर लाने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कि यह मुद्दा दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से एक निष्पक्ष सुनवाई में से एक है।

7.4 . इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 अदालतों द्वारा डी. एन. ए. परीक्षणों का निर्देश देने के रास्ते में नहीं आएगी।

योग्य मामलों में आयोजित किया गया। रिलायंस को दीपानविता रॉय बनाम रोनोब्रतो रॉय, (2015) 1 एस. सी. सी. 365 के मामले में इस अदालत के फैसले पर यह तर्क देने के लिए रखा गया था कि इस अदालत ने उक्त मामले में प्रक्रिया निर्धारित की थी

डी. एन. ए. परीक्षणों को निर्देशित करने में न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया गया, जबकि एक ही समय में साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान को संरक्षित करना। कि

वर्तमान मामले में इसी तरह के दृष्टिकोण को अपनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

7.5 . यह आगे तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, व्यभिचार के आरोपों को स्थापित करने के लिए सबूत का सबसे भौतिक टुकड़ा है

डी. एन. ए. परीक्षण और उसे संवेदनशीलता [2023] 4 एस. सी. आर. के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या गोपनीयता। शारदा में इस न्यायालय के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए भरोसा रखा गया था कि उक्त मामले में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि एक वैवाहिक अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का आदेश देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में परिकल्पित है। इसलिए, डी. एन. ए. परीक्षण की अनुमति देने के लिए अपीलार्थी की अनिच्छा और हिचकिचाहट उसके खिलाफ व्यभिचार के आरोपों की पुष्टि करती है और उक्त डी. एन. ए. परीक्षण करने की आवश्यकता को सामने लाती है।

7.6 . कि परिवार न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सामने लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डी. एन. ए. परीक्षण का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया

उन्होंने कहा कि अदालत और उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सही पुष्टि की है। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर निजी तौर पर किए गए डी. एन. ए. परीक्षण की रिपोर्ट, स्पष्ट शब्दों में, प्रतिवादी के नाबालिग बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना को खारिज करती है। ने कहा कि

रिपोर्ट डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश के लिए एक आवेदन को स्थानांतरित करने का सहारा लेने के लिए दृढ़ता से नींव रखती है। कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के तहत, परिवार न्यायालयों को किसी भी रिपोर्ट, बयान, दस्तावेजों और जानकारी पर विचार करने के लिए विशाल शक्तियां दी गई हैं जो न्यायालय को विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता कर सकती हैं और इस प्रकार, परिवार न्यायालय निजी तौर पर रिपोर्ट को स्वीकार करने में सही था।

डी. एन. ए. परीक्षण किया। उपरोक्त कथनों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि तत्काल अपील को योग्यता से रहित होने और प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में खारिज कर दिया जाए

विधि, और आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ परिवार न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाए।

विचार के लिए बिंदु:

संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, और रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होंगे:

आई.

बॉम्बे के न्यायालय ने मास्टर "एक्स" का डी. एन. ए. परीक्षण करने का निर्देश देने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 की सराहना की है। क्या, अपीलार्थी की ओर से अनुपालन न करने पर

ii.

मास्टर "एक्स" का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश, आरोप

उसके विरुद्ध व्यभिचार का निर्धारण परणा अजिंक्या फिरोदिया V. का चित्रण करके किया जा सकता है।

अर्जिक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

एक प्रतिकूल अनुमान जैसा कि चित्रण (एच) के तहत विचार किया गया है

धारा 114 का?

कौन सा आदेश?

iii.

कानूनी योजना:

8. एक आसान और तत्काल संदर्भ के लिए, प्रासंगिक प्रावधान

साक्ष्य अधिनियम यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 4. 'निर्णायक प्रमाण '। — जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निर्णायक प्रमाण घोषित किया जाता है, तो न्यायालय, एक तथ्य के प्रमाण पर, दूसरे को सिद्ध मानेगा, और साक्ष्य की अनुमति नहीं देगा। इसे अस्वीकार करने के उद्देश्य से दिया जाना।

एक्स एक्स एक्स

112. विवाह के दौरान जन्म, वैधता का निर्णायक प्रमाण।

यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अपनी माँ और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के जारी रहने के दौरान पैदा हुआ था, या इसके विघटन के दो सौ अस्सी दिनों के भीतर, माँ अविवाहित रहना, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि वह उस व्यक्ति का वैध पुत्र है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुँच नहीं थी जब तक कि वह पैदा हो सकता था।

एक्स एक्स एक्स 114। न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है। - न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि

विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में। न्यायालय अनुमान लगा सकता है कि

XXX

(ज) कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह कानून द्वारा मजबूर नहीं है, तो उत्तर, यदि दिया जाता है, तो उसके लिए प्रतिकूल होगा;

एम. पी. टी. एन. बनाए जाने चाहिए। ऐसी ही एक धारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत पितृत्व का निर्णायक विकल्प है। अनुभागकानून के नियम का पालन करता है कि निरंतरता के दौरान एक बच्चे का जन्म [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैध विवाह का या उसके विघटन के बाद 280 दिनों के भीतर (यानी गर्भधारण की अवधि के भीतर) "निर्णायक प्रमाण" होगा कि बच्चा वैध है।

जब तक कि यह साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है कि पति और पत्नी की किसी भी समय एक-दूसरे तक कोई पहुंच नहीं थी या नहीं हो सकती थी जब बच्चे की कल्पना की जा सकती थी। इस प्रावधान का उद्देश्य वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को निर्विवाद वैधता प्रदान करना है। जब वैध विवाह के दौरान एक बच्चे का जन्म होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि माता-पिता की एक-दूसरे तक पहुंच थी। इसलिए, यह धारा वैध विवाह की अवधि के दौरान बच्चे के वैध जन्म के "निर्णायक प्रमाण" की बात करती है।

धारा का अंतिम भाग प्रमाण के संदर्भ में है -

बच्चे के माता-पिता की एक-दूसरे तक पहुँच न होना। इस प्रकार, बच्चे के जन्म की वैधता की धारणा का जोरदार तरीके से खंडन किया जा सकता है इसके विपरीत प्रमाण।

धारा 112 में अंतर्निहित सिद्धांत उस बच्चे के पितृत्व के बारे में अनुचित जांच को रोकने के लिए है, जिसके माता-पिता, प्रासंगिक रूप से

समय एक-दूसरे तक "पहुँच" रखता था। दूसरे शब्दों में, एक बार जब किसी विवाह को वैध माना जाता है, तो उस विवाह से पैदा हुए बच्चों के वैध होने के बारे में एक मजबूत धारणा है। इस धारणा का खंडन केवल इसके विपरीत मजबूत, स्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 शाम लाल बनाम संजीव कुमार, (2009) 12 एस. सी. सी. 454 द्वारा सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक नीति की धारणा पर आधारित है। चूंकि धारा 112 वैधता की धारणा पैदा करती है कि विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाता है, इसलिए बच्चे की वैधता पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति पर बोझ डाला जाता है।

8.2 . इसके अलावा, "पहुँच" या "गैर-पहुँच" का मतलब वास्तविक सह-निवास नहीं है, बल्कि इसका मतलब अवसरों का "अस्तित्व" या "अस्तित्वहीन" है।

यौन संबंध के लिए। धारा 112 जन्म के समय को महत्वपूर्ण पहलू के रूप में संदर्भित करती है न कि गर्भधारण के समय के रूप में। गर्भधारण का समय केवल यह देखने के लिए प्रासंगिक है कि पति की पत्नी तक पहुंच थी या नहीं। इस प्रकार, विवाह के जारी रहने के दौरान जन्म वैधता का "निर्णायक प्रमाण" है जब तक कि बच्चे के जन्म के समय बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाने वाले पक्ष की "गैर-पहुँच" उक्त पक्ष द्वारा साबित नहीं की जाती है।

8.3 . इस संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे की वैधता के प्रमाण के संदर्भ में "निर्णायक प्रमाण" क्या है, जैसे -

साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में कहा गया है। जहां तक "निर्णायक प्रमाण" के अर्थ का संबंध है, साक्ष्य की धारा 4 का संदर्भ ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्या फिरुडिया V.

अधिनियम, जिसमें यह प्रावधान है कि जब एक तथ्य को दूसरे का निर्णायक प्रमाण घोषित किया जाता है, तो एक तथ्य का प्रमाण स्वचालित रूप से दूसरे तथ्य को साबित कर देगा, जब तक कि इस तरह से साबित किए गए तथ्य को गलत साबित करने के उद्देश्य से विपरीत साक्ष्य नहीं दिया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को धारा 4 के तहत "निर्णायक प्रमाण" की परिभाषा के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को वैध बच्चा माना जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह दिखाया गया है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा पैदा हो सकता था या विवाह के विघटन के 280 दिनों के भीतर और माँ अविवाहित रहती है, यह तथ्य निर्णायक प्रमाण है कि बच्चा पुरुष का वैध बेटा है। संबंधित समय पर गैर-पहुंच साबित करके निर्णायक धारणा के संचालन से बचा जा सकता है।

8.4 . साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के बाद के भाग से संकेत मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति यह स्थापित करने में सक्षम है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा पैदा हो सकता था, तो ऐसे बच्चे की वैधता से इनकार किया जा सकता है। अर्थात्, यह मजबूत और ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि गंभीर बीमारी या नपुंसकता के कारण उनके बीच पहुंच असंभव थी या उस अवधि के दौरान पक्षों के बीच यौन संबंध की कोई संभावना नहीं थी जब बच्चा पैदा हुआ होगा। इस प्रकार, जब तक पहुंच की अनुपस्थिति स्थापित नहीं होती है, वैधता की धारणा को विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, जहां पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, और कोई नपुंसकता साबित नहीं होती है, तो उनके विवाह से पैदा हुआ बच्चा निर्णायक रूप से होता है।

उसी समय, बेवफाई का दोषी। यह तथ्य कि एक महिला व्यभिचार में रह रही है, अपने आप में एक बच्चे की वैधता के पक्ष में निर्णायक धारणा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, इस प्रभाव के साक्ष्य के टुकड़े कि पति ने गर्भधारण की अवधि में पत्नी के साथ संभोग नहीं किया था, केवल विवाह में पैदा हुए बच्चे की अवैधता की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन यह धारा 112 के तहत वैधता की धारणा को उखाड़ नहीं पाएगा।

8.5 . धारा 112 के तहत अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब बच्चा एक वैध विवाह के जारी रहने के दौरान पैदा हुआ हो और अन्यथा नहीं। अभिगम "या" गैर-अभिगम "यौन संभोग के संदर्भ में होना चाहिए जो यौन अर्थ में है और इसलिए, उस संकीर्ण अर्थ में। उदाहरण के लिए, पहुँच असंभव हो सकती है, न केवल तब जब पति उस अवधि के दौरान दूर हो जब बच्चा पैदा हो सकता था या [2023] 4 एस. सी. आर. के कारण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभिन्न कारणों से नपुंसकता या अक्षमता या पति की मृत्यु के बाद से समय बीतना। इस प्रकार, भले ही पति सहवास कर रहा हो, लेकिन पति और पत्नी के बीच गैर-पहुंच हो सकती है।

पत्नी को। सह-निवास के बावजूद गैर-पहुंच के उदाहरणों में से एक पति की नपुंसकता है। यदि पति के पास पहुंच है, तो पत्नी की ओर से व्यभिचार अवैधता के निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएगा।

8.6 . इस प्रकार, "गैर-पहुंच" को मुद्दे में एक तथ्य के रूप में साबित करना होगा और इसे प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। एक स्पष्ट चरित्र। इस प्रकार, सह-निवास के बावजूद पति और पत्नी के बीच "गैर-पहुंच" हो सकती है। इसके विपरीत, यहाँ तक कि

वास्तविक सह-निवास के अभाव में, वहाँ पहुँच हो सकती है।

गर्भधारण के समय और पत्नी एक साथ रह रहे थे, लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण से पता चलता है कि बच्चे का जन्म पति से नहीं हुआ था। जो साबित होगा, वह पत्नी की ओर से व्यभिचार है, हालाँकि, बच्चे की वैधता अभी भी कानून में निर्णायक होगी। दूसरे शब्दों में, एक वैध विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे के पितृत्व की निर्णायक धारणा यह है कि बच्चा पति का है और इसका खंडन केवल डीएनए परीक्षण रिपोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिसका खंडन करना आवश्यक है वह उस समय गैर-पहुंच का प्रमाण है जब बच्चे का जन्म हो सकता था, यानी, इसकी गर्भधारण के समय।-कामती देवी बनाम पोशी राम, (2001) 5 एस. सी. सी. 311।

9. मामले का अगला पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या धारा 114 के चित्रण (ज) की प्रकृति में पत्नी के व्यभिचारी आचरण के बारे में एक प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है, जब वह बच्चे को डी. एन. ए. परीक्षण से गुजरने के निर्देश का पालन करने से इनकार करती है।

9.1 . धारा 114 में कहा गया है कि न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है जो उसे लगता है कि हुआ है।

किसी विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय का सामान्य पाठ्यक्रम। मोटे तौर पर, अनुमानों के दो वर्ग हैं, अर्थात् तथ्य का अनुमान और कानून का अनुमान। उत्तरार्द्ध को फिर से "कानून के खंडन योग्य अनुमानों" और "कानून के निर्विवाद या निर्णायक अनुमानों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ता, जे.]

न्यायालय यह मान सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह कानून द्वारा मजबूर नहीं है, तो उत्तर दिया जाएगा। उसे नापसंद करें। वे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है

कानून द्वारा, धारा 121-129 में निपटा जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करना आम तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष के लिए एक वैध आधार है जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। यदि कोई गवाह प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, तो न्यायालय के पास साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 (4) के माध्यम से इस तरह के इनकार से निष्कर्ष निकालने की शक्ति है। धारा 148 (4) निम्नानुसार है:

" 148. न्यायालय यह तय करेगा कि प्रश्न कब पूछा जाएगा और

जब गवाह जवाब देने के लिए मजबूर हो।

यदि ऐसा कोई प्रश्न किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो वाद या कार्यवाही से प्रासंगिक नहीं है, सिवाय इसके कि यह गवाह के श्रेय को प्रभावित करता है।

उसके चरित्र को चोट पहुँचाकर, न्यायालय यह तय करेगा कि गवाह को इसका जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा या नहीं, और यदि वह उचित समझता है, तो गवाह को चेतावनी दे सकता है कि वह इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। व्यायाम में

अपने विवेकाधिकार पर, न्यायालय को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

विचार:

XXX

न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो गवाह के इनकार से इनकार कर सकता है।

(4)

उत्तर देने के लिए, यह अनुमान कि यदि उत्तर दिया जाए तो यह होगा

प्रतिकूल "।

"हो सकता है" शब्द के प्रयोग का अर्थ होगा कि न्यायालय के पास इस तरह का निष्कर्ष निकालने का विवेकाधिकार है और वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

न्यायालय को प्रत्येक स्वतंत्र मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करना है।

9.2 . एक निष्कर्ष पर पहुँचने के उद्देश्य से, न्यायालय कर सकता है

एक तथ्यात्मक अनुमान पर भरोसा करें जब तक कि अनुमान को गलत या खारिज या खंडन नहीं किया जाता है। हालाँकि, धारा 114 के चित्रण (एच) ने न्यायालय को कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त विवेकाधीन शक्ति दी है। तथ्यों को। इस धारा के तहत अनुमान विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। उक्त प्रावधान में "अनुमान लगाया जा सकता है" वाक्यांश का उपयोग इंगित करता है कि न्यायालयों को विशेष तथ्यों के प्रभाव का न्याय करने में और यह निर्धारित करने में कि क्या उससे कोई अनुमान लगाया जाना है, अपनी समझ और अनुभव का उपयोग करना है।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इस मोड़ पर, निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है

यह न्यायालय दीपानविता राय में है जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 और 114 के बीच परस्पर क्रिया पर चर्चा की गई है। उक्त मामला प्रत्यर्थी-पति द्वारा व्यभिचार और बेवफाई के आधार पर शुरू की गई तलाक की कार्यवाही से उत्पन्न हुआ। प्रत्यर्थी का मामला यह था कि उस समय जब बच्चे की कल्पना की गई थी, जिसके पितृत्व का सवाल था, पक्षकार सह-निवास में नहीं रह रहे थे और किसी भी अवसर पर एक बिस्तर साझा नहीं कर रहे थे। प्रत्यर्थी ने डी. एन. ए. परीक्षण के माध्यम से यह स्थापित करने की मांग की कि उक्त अवधि के दौरान गर्भ धारण करने वाला बेटा विवाह से बाहर पैदा हुआ था और अपीलार्थी के परिणामस्वरूप-पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यभिचार संबंध था और परिणामस्वरूप अपीलार्थी पत्नी की ओर से बेवफाई का प्रदर्शन किया गया था। इस न्यायालय ने प्रतिवादी-पति की याचिका पर ध्यान दिया कि

प्रासंगिक समय पर गैर-पहुंच, और तदनुसार राय दी कि यह निर्देश देने के लिए एक उपयुक्त मामला होगा कि एक डी. एन. ए. परीक्षण किया जाए। इसके अलावा, उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि डी. एन. ए. परीक्षण ही एकमात्र तरीका होगा जिसमें प्रतिवादी-पति अपीलार्थी-पत्नी की ओर से अपनी बेवफाई की याचिका को स्थापित कर सकता है। नाबालिग बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने आगाह किया कि यदि इस तरह के परीक्षण के निर्देश से बचा जा सकता है, तो इससे बचा जाना चाहिए और बच्चे की वैधता को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। उक्त मामले में निर्णय के प्रासंगिक भागों को नीचे उपयोगी रूप से निकाला गया है:

" 10. भवानी प्रसाद जेना (ऊपर) और नंदलाल वासुदेव बदवैक (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से यह पता चलता है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

मामले में, किसी न्यायालय के लिए यह अनुमति होगी कि वह आरोप (आरोपों) की सत्यता निर्धारित करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दे, जो उन आधारों में से एक है, जिन पर संबंधित पक्ष या तो सफल होगा या हार जाएगा। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि इस तरह के परीक्षण के निर्देश से बचा जा सकता है, तो इससे बचा जाना चाहिए। इसका कारण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में पहले ही दर्ज किया जा चुका है, यह है कि बच्चे की वैधता को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।

11. इस मामले में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह अपीलार्थी-पत्नी की कथित बेवफाई के संबंध में है। प्रतिवादी पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर याचिका में स्पष्ट और स्पष्ट दावे किए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि

बेवफाई। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम रखने तक का काम किया है, जो अपीलार्थी की पत्नी से पैदा हुए पुरुष बच्चे का पिता था। यह उनके बेवफाई के आरोप को साबित करने की प्रक्रिया में है, कि परणा अजिंक्य फिरडिया बनाम।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

प्रत्यर्थी-पति ने डीएनए परीक्षण करने के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया था, जो यह स्थापित करेगा कि क्या

या नहीं, उसने अपीलार्थी-पत्नी से पैदा हुए पुरुष बच्चे को जन्म दिया था। प्रत्यर्थी को लगता है कि उसके लिए केवल डीएनए परीक्षण के माध्यम से उसके द्वारा लगाए गए आरोपों (अपीलार्थी-पत्नी की बेवफाई) को साबित करना संभव है। हम उनसे सहमत हैं। हमारे विचार में, लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण के लिए, प्रतिवादी-पति के लिए अभिवचनों में किए गए दावों को स्थापित और पुष्टि करना असंभव होगा। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश, जैसा कि यहाँ ऊपर निकाला गया है, पूरी तरह से उचित था। डी. एन. ए. परीक्षण सबसे वैध और वैज्ञानिक रूप से सही साधन है, जिसका उपयोग पति अपनी बेवफाई के दावे को स्थापित करने के लिए कर सकता है। इसे साथ ही पत्नी के लिए भी सबसे प्रामाणिक, सही और सही साधन के रूप में लिया जाना चाहिए, ताकि वह प्रतिवादी-पति द्वारा किए गए दावों का खंडन कर सके और यह स्थापित कर सके कि वह विश्वासघाती, व्यभिचारी या विश्वासघाती नहीं थी। यदि अपीलार्थी-पत्नी सही है, तो वह सही साबित होगी।

12. हालाँकि, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, एक चेतावनी दर्ज करना उचित और उचित समझेंगे, जिससे अपीलकर्ता-पत्नी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने या उसकी अवहेलना करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें डी. एन. ए. परीक्षण आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यदि वह उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को स्वीकार करती है,

डी. एन. ए. परीक्षण निर्णायक रूप से सच्चाई का निर्धारण करेगा

प्रत्यर्थी द्वारा लगाया गया आरोप-पति, उसके खिलाफ। यदि वह उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश का पालन करने से इनकार करती है, तो आरोप का निर्धारण संबंधित न्यायालय द्वारा धारा में अनुध्यात प्रकृति का अनुमान लगाकर किया जाएगा।

114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विशेष रूप से, उसके चित्रण (ज) के संदर्भ में। धारा 114, उदाहरण (ज) के रूप में भी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है,

इन्हें नीचे निकाला जा रहा है:

" 114. न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है-न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है जो उसे लगता है कि प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए,

विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में।

चित्रण (एच)-कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह कानून द्वारा मजबूर नहीं है, तो उत्तर, यदि दी गई, उसके लिए प्रतिकूल होगी। "[2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार को यथासंभव संरक्षित करने के लिए अपनाया गया है। बेशक, न्याय के कारण का त्याग किए बिना। उपरोक्त पाठ्यक्रम को अपनाने से, भारतीय संविधान की धारा 112 के तहत परिकल्पित धारणा को स्पष्ट रूप से बाधित किए बिना, केवल बेवफाई के मुद्दे का निर्धारण किया जाएगा।

साक्ष्य अधिनियम। भले ही, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, निस्संदेह वैधता का मुद्दा भी संयोग से शामिल होगा।

10.1 . हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों को दीपानविता रॉय के तथ्यों से अलग करना आवश्यक है। उक्त मामले में, प्रतिवादी

पति ने धारा 112 के तहत धारणा का खंडन करने के लिए गैर-पहुंच का एक विशिष्ट अनुरोध किया था। उन्होंने बेवफाई का आरोप लगाते हुए दायर याचिका में स्पष्ट और स्पष्ट दावे किए। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम भी रखा जो अपीलार्थी से पैदा हुए पुरुष बच्चे का पिता था-पत्नी, और जोर देकर कहा कि प्रासंगिक समय पर, वह और उनकी पत्नी किसी भी अवसर पर बिस्तर साझा नहीं करते थे। उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, व्यभिचार/बेवफाई के आरोपों को साबित करना असंभव होता।

डीएनए परीक्षण। हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी-पति द्वारा किसी को हटाने के लिए गैर-पहुंच के रूप में कोई याचिका नहीं उठाई गई है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान। इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से दावा किया है कि उसके पास कॉल है

रिकॉर्डिंग/प्रतिलेख, और अपीलार्थी की दैनिक डायरी, जो अपीलार्थी की बेवफाई की ओर इशारा करती है। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थी के व्यभिचार के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण ही एकमात्र संभावित तरीका होगा। इसलिए, वर्तमान मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को हटाने और मास्टर "एक्स" के डीएनए परीक्षण की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त सामग्री है।

इसके अलावा, सत्य को स्थापित करने के लिए उक्त मामले में डी. एन. ए. परीक्षण की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता-पत्नी डी. एन. ए. परीक्षण के संबंध में न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इनकार करती है, तो उसके खिलाफ व्यभिचार के आरोपों का निर्धारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (एच) के तहत एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर किया जाएगा। हालाँकि, उक्त मामले में किए गए इस तरह के अवलोकन को एक मिसाल नहीं माना जा सकता है। जिसे सभी मामलों में स्ट्रेट जैकेट तरीके से लागू किया जा सकता है जिसमें पत्नी डीएनए परीक्षण के संबंध में न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इनकार करती है।

इस मोड़ पर इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनुमान तथ्यों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, और न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, या तो ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

एक तथ्य का अनुमान लगाना या नहीं। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, दीपानविता राय में तथ्य इतने सम्मोहक थे, कि डीएनए परीक्षण करने के निर्देश को उचित ठहराने के लिए। उक्त मामले में, पति ने गैर-पहुँच का एक विशिष्ट अनुरोध लिया था। इसके अलावा, अदालत ने स्वीकार किया कि एक डीएनए परीक्षण होगा

केवल ऐसा तरीका जिसमें व्यभिचार का मामला साबित किया जा सके। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्य न तो मास्टर "एक्स" का डी. एन. ए. परीक्षण करने के निर्देश की गारंटी देते हैं, और न ही वे अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत, अपने बेटे को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन करने से इनकार करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने को उचित ठहराते हैं।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 9 वें संस्करण के अनुसार, 'अनुमान' का अर्थ है "अन्य तथ्यों पर विचार करके और निष्कर्ष निकालकर पहुँचा गया निष्कर्ष।

उनसे तार्किक परिणाम।

'प्रतिकूल अनुमान' की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

" तथ्य द्वारा तैयार किया गया एक हानिकारक निष्कर्ष-किसी पक्ष की सबूत पेश करने में विफलता से खोजकर्ता जो पक्ष के नियंत्रण में है। कुछ अदालतें केवल तभी निष्कर्ष की अनुमति देती हैं जब पक्षकार

असफलता के लिए बुरे विश्वास को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त अर्थ यह भी सुझाव देगा कि निष्कर्ष, चाहे प्रतिकूल हों या अन्यथा, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पर विचार करने पर निकाले जाने चाहिए:

प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। इसलिए दिया गया फैसला

दीपानविता राय में इस न्यायालय के आदेश को उपरोक्त संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। तत्काल मामले में, मास्टर "एक्स" के पितृत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है क्योंकि बहस के दौरान भी, विद्वान वरिष्ठ वकील

श्री कपिल सिब्बल ने स्वीकार किया कि मास्टर "एक्स" का जन्म पार्टियों के निरंतर सहवास के दौरान और इस प्रकार एक वैध विवाह के निर्वाह के दौरान हुआ था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल की दलीलों का जोर इस बात पर था कि यदि अपीलकर्ता विषय के लिए सहमत नहीं है

डी. एन. ए. परीक्षण के लिए मास्टर "एक्स", फिर, उसके व्यभिचारी जीवन के बारे में उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष की प्रकृति क्या हो सकती है? प्रतिकूल निष्कर्ष मास्टर "एक्स" के विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चे और इसलिए एक अवैध बच्चे के संबंध में नहीं है। जो तर्क दिया गया था वह यह था कि अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार के संबंध में एक प्रतिकूल निष्कर्ष

यहाँ उठाया जा सकता है। हम इस मामले में इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते। मास्टर "एक्स" के पितृत्व का मुद्दा इसमें अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार के मुद्दे से अलग है। मास्टर "एक्स" यहाँ

पक्षों का एक वैध बच्चा होने के नाते [2023] 4 एस. सी. आर. पर कथित व्यभिचार से कोई लेना-देना नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें अपीलार्थी का भाग। इसलिए, दीपानविता राय में इस न्यायालय का निर्णय प्रतिवादी के लिए कोई सहायक नहीं है। उपरोक्त मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर बदल जाता है और इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक मिसाल के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

व्यभिचार साबित करने के लिए डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग तकनीक का उपयोग:

11. विज्ञान की प्रगति के साथ, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग प्रौद्योगिकी जो फोरेंसिक विज्ञान का एक उपकरण है, किसी व्यक्ति के विवादित पितृत्व के मामले में हो सकती है। अपने माता-पिता के साथ बच्चे के शरीर के तरल पदार्थ या शरीर के ऊतकों से प्राप्त डी. एन. ए. की केवल तुलना करके, जैविक माता-पिता के अचूक प्रमाण प्रदान करता है। लेकिन, यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई विशेष बच्चा किसी विशेष व्यक्ति से पैदा हुआ था, डीएनए परीक्षण करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है।

हालाँकि, सबूत का भार उस पति पर है जो अवैधता का आरोप लगाता है। उसे इस तथ्य को स्थापित करना होगा कि उसने अपनी पत्नी से पैदा हुए बच्चे को जन्म नहीं दिया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार सकारात्मक सबूत द्वारा एक नकारात्मक याचिका है। 11.1 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक परिवार न्यायालय के पास किसी व्यक्ति को डी. एन. ए. परीक्षण सहित चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का निर्देश देने की शक्ति है और इस तरह का आदेश होगा

शारदा के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हालाँकि, न्यायालय को ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब ऐसा करना न्याय के हित में समीचीन हो, और जब किसी दिए गए मामले में तथ्य की स्थिति इस तरह के प्रयोग की आवश्यकता हो। इस प्रकार, एक आदेश जिसमें निर्देश दिया गया है कि एक नाबालिग बच्चे को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन किया जाए, प्रत्येक मामले में यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। 11.2 . इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 से जुड़े प्रश्नों पर विचार करते हुए, केवल पूछने पर डी. एन. ए. परीक्षण का आदेश दिए जाने के खिलाफ लगातार रुख व्यक्त किया है। इसके अलावा, कानून पितृत्व निर्धारित करने के लिए खोज या जांच प्रयोगों के रूप में डी. एन. ए. परीक्षणों के उपयोग पर विचार नहीं करता है। इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय उन परिस्थितियों को निर्धारित करने में अत्यधिक शिक्षाप्रद हैं जिनके तहत पितृत्व के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामलों में न्यायालय द्वारा डी. एन. ए. परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है:

आई.

गौतम कुंडू में, इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता थी

क्या एक नाबालिग बच्चे के रक्त परीक्षण को पितृत्व के विवादित प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए एक साधन के रूप में आयोजित करने का आदेश दिया जा सकता है जो अनिवार्य रूप से रखरखाव से संबंधित एक वैवाहिक विवाद था। उक्त मामले में, अपीलार्थी पति ने उसमें बच्चे के पितृत्व पर विवाद किया और ए अजिंक्या फिरुडिया बनाम की प्रार्थना की।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ता, जे.]

यह साबित करने के लिए कि वह बच्चे का पिता नहीं था, बच्चे के रक्त समूह परीक्षण के लिए। उनके अनुसार, यदि यह स्थापित किया जा सकता है, तो वह रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विवाह के निर्वाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता के अनुमान को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत व्यक्त किया गया है। रक्त का निर्देशन करने की न्यायालयों की शक्ति पर उक्त धारणा का परिणाम वैवाहिक विवादों में पितृत्व निर्धारित करने के साधन के रूप में परीक्षण पर इस न्यायालय द्वारा चर्चा की गई थी, और निम्नलिखित सिद्धांत

" 26. उपरोक्त चर्चा से यह सामने आता है: (1)

भारत में अदालतें एक मामले के रूप में रक्त परीक्षण का आदेश नहीं दे सकती हैं

बेशक;

जहाँ भी ऐसी प्रार्थनाओं के लिए आवेदन किए जाते हैं

(2)

रोविंग इन्क्वायरी करने का आदेश, रक्त परीक्षण के लिए प्रार्थना

मनोरंजन नहीं किया जा सकता।

इसमें एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए कि

(3)

पति को धारा 112 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा को दूर करने के लिए गैर-पहुंच स्थापित करनी चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम।

(4)

अदालत को सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए कि क्या होगा

यह रक्त परीक्षण का आदेश देने का परिणाम होगा; क्या इसका प्रभाव एक बच्चे को कमीने और माँ को अपवित्र महिला के रूप में ब्रांडिंग करने पर पड़ेगा।

किसी को भी रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(5)

विश्लेषण "।

भबानी प्रसाद जेना में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे के पितृत्व को निर्धारित करने के लिए डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग तकनीक का उपयोग करने का निर्देश एक अत्यंत नाजुक और संवेदनशील पहलू है। इसलिए, ऐसे परीक्षणों को निर्देशित किया जाना चाहिए

केवल तभी आयोजित किया जाता है जब उनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। एक बच्चे के पितृत्व से संबंधित मामले में वह डीएनए प्रोफाइलिंग जब भी ऐसा अनुरोध किया जाता है तो अदालत द्वारा निश्चित रूप से या नियमित तरीके से निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा।

ऐसा आदेश और 'प्रमुख आवश्यकता' का परीक्षण कि क्या न्यायालय के लिए इस तरह के परीक्षण के उपयोग के बिना सच्चाई तक पहुंचना संभव नहीं है। यह आगे घोषित किया गया कि एक अदालत निर्देश दे सकती है कि पितृत्व को निर्णायक रूप से निर्धारित करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण किया जाए, केवल तभी जब इस तरह के निर्देश की मांग करने वाले व्यक्ति के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला हो।

इनायत अली बनाम तेलंगाना राज्य, एम. ए. एन. यू./एस. सी./1538/2022 के मामले में, इस अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या अदालत द्वारा दो नाबालिग बच्चों के डी. एन. ए. परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है, ताकि धाराओं के तहत आरोपों के सबूत को सुविधाजनक बनाया जा सके। 498 भारतीय दंड संहिता, 1860 का ए, 323,354,506 और 509। इस न्यायालय ने शुरुआत में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के माध्यम से बोलते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विवाद अनिवार्य रूप से दहेज से संबंधित अपराधों से संबंधित था, और शिकायतकर्ता के बच्चों का पितृत्व सीधे आरोपों से संबंधित नहीं था। उसमें शिकायतकर्ता ने अपने दो नाबालिग बच्चों का डी. एन. ए. परीक्षण करने का निर्देश देने की मांग की, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि वे अपने बहनोई के साथ उसके जबरन संबंध के परिणामस्वरूप पैदा हुए थे। खारिज करते हुए

शिकायतकर्ता की याचिका में, इस न्यायालय ने बच्चों के डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन करने की अदालतों की शक्ति के तहत अभिनिर्धारित किया, ऐसी कार्यवाही में जिसमें उनकी स्थिति की जांच करने की आवश्यकता नहीं है:

"वर्तमान कार्यवाही में, हम दो कारकों को ले रहे हैं

जिनका विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी उपेक्षा की गई है। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नं. 2 यांत्रिक रूप से, इस आधार पर कि कानून के तहत डीएनए फिंगरप्रिंट परीक्षण की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने भी दीपानविता राय बनाम के मामले सहित विभिन्न प्राधिकरणों का हवाला देते हुए उस आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया है। रोनोब्रोदो रॉय [2015 (1) एस. सी. सी. 365]। अशोक कुमार के फैसले में समन्वय पीठ ने भी इस मामले के अनुपात की जांच की थी। (ऊपर)।

7. पहला कारक, जो हमारी राय में, महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अपील के तहत दिए गए फैसले में, बच्चों के रक्त के नमूने लेने का निर्देश दिया गया था, जिसे जिन्क्या फिरुडिया बनाम।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ता, जे.]

वे कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे और न ही प्रत्यर्थी सं. की शिकायत में उनकी स्थिति की जांच करने की आवश्यकता थी। 2 . इससे उन पर संदेह पैदा हो गया कानूनी रूप से विवाहित माता-पिता को जन्म देने की वैधता और ऐसे निर्देश, यदि किए जाते हैं, तो उनमें विरासत से संबंधित जटिलताओं को उजागर करने की क्षमता होती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 भी इस तरह के आरोपों से सुरक्षा प्रदान करती है। उक्त प्रावधान में कहा गया है:

" विवाह के दौरान जन्म, निर्णायक प्रमाण

वैधता। यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अपनी माँ और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ था, या उसके विघटन के दो सौ अस्सी दिनों के भीतर, माँ अविवाहित रहना, निर्णायक प्रमाण होगा कि वह उस व्यक्ति का वैध पुत्र है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक कोई पहुंच नहीं थी।

जब उसका जन्म हो सकता था।

विश्लेषण करें। दूसरी बात, हमारी राय में, जिसे उक्त दो न्यायालयों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, वह यह है कि इस विषय में बच्चों के पितृत्व पर कोई सवाल नहीं था आगे बढ़ रहे हैं।

1860 की संहिता के प्रावधान उनके खिलाफ किए गए थे या नहीं। प्रतिवादी की दो बेटियों का पितृत्व सं. 2 एक संपार्श्विक कारक है आरोप जिन पर आपराधिक मामला अन्यथा आधारित है। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, हमारी राय में, जिस मामले से यह कार्यवाही उत्पन्न होती है, उसका निर्णय डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट पर विचार किए बिना किया जा सकता है। यह वह तर्क था जिसे [2023] 4 एस. सी. आर. माना गया था।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अशोक कुमार के मामले में समन्वय पीठ द्वारा

(ऊपर), हालांकि वह एक दीवानी मुकदमा था। सिर्फ इसलिए कि

कानून के तहत कुछ अनुमत नहीं है
निष्पादित करने के लिए एक मामले के रूप में निर्देशित

निश्चित रूप से

विशेष रूप से जब उस प्रभाव की दिशा होगी

किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता के लिए आक्रामक होना।

इसका परिणाम इन तक ही सीमित नहीं रहेगा -

सवाल यह है कि क्या इस तरह के आदेश का परिणाम होगा

प्रशंसात्मक मजबूरी, लेकिन इसमें निजता का अधिकार शामिल है

ऐसे परीक्षणों के अधीन व्यक्तियों का अधिकार और
दोनों बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

यह

जिन्हें भी दायरे में लाने की मांग की गई थी

ट्रायल कोर्ट के निर्देश "।

(हम पर जोर दें)

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित

उन परिस्थितियों के बारे में बताया जाए जिनके तहत

च एकटा नाबालिक बच्चा के संचालित करवाक निर्देश देल जा सकैत अछि:

नियमित रूप से, वैवाहिक विवादों में। डीएनए के माध्यम से प्रमाण
विवादों में निर्देशित किया जाना है जिसमें शामिल हैं

प्रोफाइलिंग को वैवाहिक

बेवफाई के आरोप, केवल उन मामलों में जहां कोई नहीं है
अन्य तरीका।

इस तरह के दावों को साबित करने का

विवाह तभी निर्देशित किया जा सकता है जब पर्याप्त हो।
सामग्री

अनुमान को हटाने के लिए प्रथम दृष्टया

साक्ष्य अधिनियम की धारा 112। इसके अलावा, यदि कोई याचिका नहीं है

परीक्षण निर्देशित नहीं किया जा सकता है।
होगा

एक न्यायालय यांत्रिक रूप से निर्देश देने में उचित नहीं

एक बच्चे का डीएनए परीक्षण, एक ऐसे मामले में जहां एक बच्चे का पितृत्व

आगे बढ़ रहे हैं।

केवल इसलिए कि किसी भी पक्ष ने एक तथ्य पर विवाद किया है

पितृत्व के मामले में, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय को निर्देश देना चाहिए
हल करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण या ऐसा अन्य परीक्षण।

विवाद को

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

पक्षकारों को पितृत्व के तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और केवल तभी जब न्यायालय को ऐसे साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना असंभव लगता है, या मुद्दे में विवाद को डी. एन. ए. परीक्षण के बिना हल नहीं किया जा सकता है, तो वह डी. एन. ए. परीक्षण का निर्देश दे सकता है और अन्यथा नहीं। अन्य में

शब्द, केवल असाधारण और योग्य मामलों में, जहां इस तरह का परीक्षण विवाद को हल करने के लिए अपरिहार्य हो जाता है

न्यायालय इस तरह के परीक्षण का निर्देश दे सकता है।
व्यभिचार साबित करने के साधन के रूप में डी. एन. ए. परीक्षणों का निर्देशन करते हुए,

बी.

न्यायालय को इसके परिणामों के प्रति सचेत रहना है

व्यभिचार से पैदा हुए बच्चे, विरासत सहित

संबंधित परिणाम, सामाजिक कलंक, आदि।

13. इसके अलावा, नंदलाल वासुदेव बदवैक में, मामले के तथ्य थे कि पत्नी के वकील के गैर-विरोध के कारण, इस अदालत ने निर्देश दिया कि सीरोलॉजिकल परीक्षण किया जाए। रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता-पति नाबालिग बच्चे का जैविक पिता नहीं था। प्रत्यर्थी के अनुरोध पर-पत्नी, फिर से

परीक्षण का आदेश दिया गया था, जिससे भी वही परिणाम सामने आया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के लागू होने के संबंध में याचिका इस न्यायालय के निर्देश पर डीएनए परीक्षण किए जाने और रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाए जाने के बाद ही ली गई थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब किसी न्यायालय के निर्देश पर किए गए डी. एन. ए. परीक्षण की रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध थी और बच्चे की वैधता के निर्णायक प्रमाण की धारणा के साथ टकराव में थी, तो डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय ने डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया और कहा कि अपीलार्थी-पति भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उक्त मामला यहाँ प्रत्यर्थी के मामले में कोई सहायता नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि, उक्त मामले में, इस न्यायालय को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जिसमें डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट, वास्तव में, उपलब्ध थी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत बच्चे की वैधता के निर्णायक प्रमाण के अनुमान के साथ संघर्ष में थी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, आज तक कोई डीएनए परीक्षण उपलब्ध नहीं है, जो एक सक्षम अदालत के निर्देश पर किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी-पति को पहले साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को हटाने की आवश्यकता होगी और

इसके बाद मास्टर 'एक्स' का डीएनए परीक्षण करने का निर्देश लें।
लिए रक्त परीक्षणों के साक्ष्य मूल्य पर रायडेन और जैक्सन ऑन डिवोर्स एंड फैमिली में चर्चा की गई है।

14. पितृत्व निर्धारित करने के

मामले, (1983) खंड। आई, पीजी में। 1054 , निम्नलिखित शब्दों में:

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" मुकदमे के प्रकार, रक्त के नमूनों के आधार पर, जब

कुशल वैज्ञानिक परीक्षण के अधीन, कभी-कभी आपूर्ति कर सकते हैं

विभिन्न मुद्दों पर सहायक साक्ष्य, माता-पिता की व्यवस्था को बाहर करने के लिए

एक बच्चा होने के दावे पर जोर देते हुए और प्रतिद्वंद्वी ने माता-पिता को स्थापित किया रक्त परीक्षण के लिए ऐसा करने के उसके अधिकार को स्थापित करना चाहिए। अदालतें अभ्यास करती हैं

एक शिशु की ओर से सुरक्षात्मक अधिकार क्षेत्र। मुझमें

राय माना जाता है, यह अन्यायपूर्ण होगा और उचित भी नहीं होगा एक वादी की सहायता के लिए एक संपार्श्विक कारण के लिए एक परीक्षण का निर्देश दें

या उसका दावा। बच्चे को पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि उसकी असमर्थता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसे अपने अधिकार मिलें।

यदि किसी मामले में अदालत के पास यह मानने का कारण है कि

कुछ गुप्त उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह उचित होगा ऐसी प्रार्थना के अनुसार नहीं "।

(हम पर

जोर दें)

15. यह मामूली बात है कि अपना पक्ष साबित करने का भार मुकदमेबाज पक्ष पर है।

उसकी याचिका के समर्थन में सबूत पेश करके मामला। अशोक कुमार के अनुसार, न्यायालय को विवाद के लिए एक पक्ष को दूसरे प्रतिद्वंद्वी पक्ष की सहायता करने के लिए मजबूर नहीं करना है। इसलिए, डी. एन. ए. परीक्षण नियमित आधार पर निर्देशित नहीं किए जाने चाहिए, केवल एक पक्ष को व्यभिचार के अपने मामले को साबित करने में सक्षम बनाने के लिए।

बच्चों की वैधता न होने के अधिकार पर सवाल उठाए गए हैं।

कानून के न्यायालयों में तुच्छ रूप से:

16. भारत में डिफ़ॉल्ट स्थिति यह है कि कई कारणों से, माता-पिता

जहाँ तक माना जाता है कि वे अपने बच्चों के लिए निर्णय निर्माता हैं

स्वास्थ्य सेवा, आनुवंशिक परीक्षण के लिए सहमति आदि का संबंध है। इस स्थिति के लिए औचित्य में यह शामिल है कि माता-पिता बहुत व्यापक सीमाओं के भीतर स्वतंत्र हैं यह तय करें कि अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे किया जाए, माता-पिता को अपने बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की सबसे अधिक

संभावना माना जाता है, बच्चों में आम तौर पर पूरी तरह से सक्षम निर्णय लेने की क्षमता की कमी होती है इसलिए किसी और को करना चाहिए, और राज्य का हस्तक्षेप शायद ही कभी उचित होता है। आनुवंशिक जानकारी व्यापक रूप से है

किसी व्यक्ति के सार पर प्रकाश डालने के रूप में समझा जाता है, जैसे कि वह जो है उसके दिल में जाना। उस तरह की अंतरंग, व्यक्तिगत जानकारी, जो हमारे समाज में बहुत मूल्यवान है, ठीक वही है जिसकी कानून सुरक्षा करता है।

निजता का अधिकार, जो बच्चों तक भी फैला हुआ है।

17. इसके अलावा, बच्चों को यह अधिकार है कि उनकी वैधता न हो

न्यायालय के समक्ष तुच्छता से पूछताछ की गई। यह एक आवश्यक विशेषता ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्या फिरुडिया वी. है।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

निजता का अधिकार। इसलिए न्यायालयों को स्वीकार करना आवश्यक है

कि बच्चों को भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं माना जाना चाहिए, और फोरेंसिक/डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब वे तलाक की कार्यवाही में पक्षकार नहीं हों। यह जरूरी है कि बच्चे पति-पत्नी के बीच लड़ाई का केंद्र बिंदु न बनें।

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत बच्चों की गोपनीयता, स्वायत्तता और पहचान के अधिकार:

18. 1989 में, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बाल अधिकारों पर सम्मेलन तैयार किया, जिसमें घोषणा की गई कि "बचपन विशेष देखभाल और सहायता का हकदार है"। घोषणा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मान्यता देती है कि एक बच्चे को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए, पारिवारिक वातावरण में, खुशी, प्रेम और समझ के वातावरण में बड़ा होना चाहिए। यह घोषणा "समाज के मौलिक समूह और इसके सभी सदस्यों और विशेष रूप से बच्चों के विकास और कल्याण के लिए प्राकृतिक वातावरण" के रूप में परिवार के महत्व पर जोर देती है।

19. कन्वेंशन का अनुच्छेद 19 बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बचाता है; अनुच्छेद 24 (3) बच्चों को पारंपरिक प्रथाओं से बचाता है जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हैं; और अनुच्छेद 37 बच्चों को यातना और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से बचाता है। इन प्रावधानों को पूरा करना एक बच्चे का निजता का अधिकार है, जो एक बच्चे की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता तक फैला हुआ है।

बच्चा। महत्वपूर्ण रूप से, इस तरह के व्यवहार पर पूर्ण निषेध को देखते हुए, एक बच्चे की शारीरिक अखंडता का उल्लंघन जो यातना या क्रूर अमानवीय अपमानजनक व्यवहार की सीमा तक पहुंच जाता है, कभी भी उचित नहीं होगा। इस प्रकार, इस निषेध का उल्लंघन हमेशा बच्चे के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हालाँकि, गोपनीयता के अधिकार का उन मामलों में एक अवशिष्ट अनुप्रयोग है जहाँ बच्चे की शारीरिक और/या मनोवैज्ञानिक अखंडता में हस्तक्षेप होता है जो यातना या क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार की सीमा तक नहीं पहुँचता है। ऐसी परिस्थितियों में सवाल यह बन जाता है कि क्या बच्चे की सत्यनिष्ठा में हस्तक्षेप वैध और गैर-मनमाना है।

20. कन्वेंशन माता-पिता के अधिकारों को समायोजित और संरक्षित करता है।

उनके बच्चों के पालन-पोषण के संबंध में, अनुच्छेद 5 के अनुसार। हालाँकि, माता-पिता की इच्छाओं का यह सम्मान इस सख्त चेतावनी के अधीन है कि ऐसे अधिकारों का प्रयोग बच्चे को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार, जब तक कि कोई अभिभावक उद्देश्य [2023] 4 एस. सी. आर. के आधार पर प्रदर्शन नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस बात का प्रमाण कि बच्चे की शारीरिक अखंडता में हस्तक्षेप का उद्देश्य बच्चे के स्वास्थ्य और विकास को लाभ पहुंचाना है, हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराया जाएगा। यदि किसी बच्चे की निजता या शारीरिक अखंडता के अधिकार में किसी भी हस्तक्षेप को उचित ठहराया जाना है, तो यह स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐसा वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है जो उपाय और उद्देश्य के बीच एक संबंध स्थापित करता है; कि कोई उचित रूप से उपलब्ध विकल्प नहीं है जो बच्चे के अधिकार में हस्तक्षेप को कम करता। कन्वेंशन में उल्लिखित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से व्यभिचार साबित करने के साधन के रूप में एक बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण करना, कन्वेंशन के तहत आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की दृष्टि से है। इसके अलावा, ऐसे मामले में बच्चे की शारीरिक अखंडता में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा, क्योंकि डीएनए परीक्षण के लिए प्रतिवादी के अनुरोध और बच्चे के सर्वोत्तम हितों के बीच कोई संबंध नहीं है।

21. एक बच्चे के लिए गोपनीयता की अवधारणा एक वयस्क के बराबर नहीं हो सकती है। हालाँकि, बच्चों की विकसित क्षमता को मान्यता दी गई है और कन्वेंशन इस नियंत्रण को स्वीकार करता है कि बच्चों सहित व्यक्तियों के पास अपनी व्यक्तिगत सीमाओं पर नियंत्रण है और जिस माध्यम से वे परिभाषित करते हैं कि वे अन्य लोगों के संबंध में कौन हैं। बच्चों को केवल बच्चे होने के कारण अपनी स्वयं की भावना को प्रभावित करने और समझने के इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कन्वेंशन का अनुच्छेद 8 बच्चों को उनके अधिकारों को संरक्षित करने का एक स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है।

पहचान। माता-पिता का विवरण बच्चे की पहचान की एक विशेषता है। इसलिए, बच्चे के माता-पिता के बारे में लंबे समय से स्वीकृत धारणाओं को अदालतों के समक्ष तुच्छ रूप से चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

एक बच्चे के सर्वोत्तम हित:

22. वाक्यांश "मानव जाति बच्चे को सबसे अच्छा देने के लिए ऋणी है" स्पष्ट रूप से बच्चों के प्रति हमारे कर्तव्यों को रेखांकित करता है, और यह उन्हें हकदार बनाता है।

सबसे अच्छा जो मानव जाति दे सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों से जुड़े कार्यों में बच्चे के हित पर प्राथमिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस विचार को बाल अधिकारों पर समझौते के अनुच्छेद 3 में प्रभावी रूप से व्यक्त किया गया है जो इस प्रकार है:

" बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में, चाहे वे जनता द्वारा किए गए हों।

या निजी समाज कल्याण संस्थान, कानून की अदालतें,

प्रशासनिक प्राधिकरण या विधायी निकाय, सर्वोत्तम हित

बच्चे पर प्राथमिक रूप से विचार किया जाएगा।

ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरुडिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. बी. नागरत्ना, जे.]

22.1 आर. ई. एल., (1968) 1 में रिपोर्ट किए गए दो अंग्रेजी निर्णयों में सभी ई. आर. 20 और बी। (बी. आर) बनाम। बी. (जे.), (1968) 2 सभी ई. आर. 1023, पितृत्व निर्धारित करने के लिए बच्चे के रक्त परीक्षण की अनुमति दी गई थी। हालांकि, निर्णय

आर. ई. एल. में इस तर्क के आधार पर पारित किया गया था कि एक रक्त परीक्षण निर्देशित किया जा सकता है यदि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में काम करता है। हालांकि, लॉर्ड डेनिंग, एम. आर. का विचार था कि पितृत्व के मुद्दों से जुड़े मामलों में या ऐसी कार्यवाही में भी रक्त परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है जहाँ बच्चे के पितृत्व को किसी न किसी तरह से निपटाना उसके सर्वोत्तम हित में हो। हालांकि, उसी निर्णय में, विल्मर, एलजे और डेवोस, एलजे ने लॉर्ड डेनिंग, एमआर की राय के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की। अभिरक्षा क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य कार्यवाही में रक्त परीक्षण।

हालांकि, बी के बाद के निर्णय में। (बी. आर.), यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पितृत्व के मुद्दे पर रक्त परीक्षण का आदेश दे सकता है या

वास्तव में किसी भी अन्य मुद्दे पर, ऐसा करते समय ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा।

22.2 इस न्यायालय ने विशेष रूप से बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित विवादों में बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को लगातार लागू किया है। 22.3 . इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अवैधता के बारे में कोई निष्कर्ष, यदि डीएनए परीक्षण में सामने आता है, तो कम से कम बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मनोवैज्ञानिक रूप से। यह न केवल बच्चे के मन में भ्रम पैदा कर सकता है लेकिन यह पता लगाने की खोज कि असली पिता कौन है और एक ऐसे व्यक्ति के प्रति मिश्रित भावना जिसने बच्चे का पालन-पोषण किया होगा लेकिन वह जैविक पिता नहीं है। यह न जानना कि किसी का पिता कौन है, बच्चे में एक मानसिक आघात पैदा करता है। कोई कल्पना कर सकता है, अगर, जैविक पिता की पहचान जानने के बाद, एक युवा मस्तिष्क पर कितना बड़ा आघात और तनाव प्रभाव डालेगा। आर. ई. एम. में होने वाली कार्यवाही का न केवल बच्चे पर बल्कि माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते पर भी वास्तविक प्रभाव पड़ता है जो अन्यथा उत्कृष्ट है। यह कहा गया है कि बच्चे के माता-पिता के पास हो सकता है

एक अवैध संबंध लेकिन इस तरह के संबंध से पैदा हुआ बच्चा अपने माथे पर अवैधता की मुहर नहीं लगा सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे की उसके जन्म में कोई भूमिका नहीं होती है। एक निर्दोष बच्चे को उसके पितृत्व की खोज करने के लिए आघात नहीं दिया जा सकता है और अत्यधिक तनाव और तनाव के अधीन नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 एक बच्चे के पितृत्व के संबंध में एक निर्णायक अनुमान के बारे में बात करती है, जो एक खंडन के अधीन है, जैसा कि धारा के दूसरे भाग में प्रदान किया गया है।

आज की दुनिया में, एक बच्चे के पितृत्व का दावा करने के लिए एक दौड़ भी हो सकती है ताकि उसके अधिकारों पर आक्रमण किया जा सके, विशेष रूप से, यदि ऐसा बच्चा संपन्न है [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आज के बच्चे नागरिक हैं और राष्ट्र का भविष्य हैं। एक बच्चे का आत्मविश्वास और खुशी जिस पर प्यार की बौछार होती है और माता-पिता दोनों का स्नेह उस बच्चे से पूरी तरह से अलग है जिसके माता-पिता नहीं हैं या जिसने माता-पिता को खो दिया है और इससे भी बदतर उस बच्चे का है जिसका माता-पिता नहीं है।

बिना किसी ठोस कारण के पितृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। एक ऐसे बच्चे की दुर्दशा, जिसका पितृत्व और इस प्रकार उसकी वैधता, अपर्णा अजिंक्य फिरडिया बनाम है।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

यदि न्यायालय अत्यधिक विवेकपूर्ण और सतर्क तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त सतर्क और जिम्मेदार नहीं हैं तो पूछताछ किए जाने पर भ्रम की एक भंवर में डूब जाएगा जिसे भ्रमित किया जा सकता है। इसके अलावा, पितृत्व से जुड़े प्रश्नों का बच्चे की पहचान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नियमित रूप से डीएनए परीक्षणों का आदेश देना, विशेष रूप से

ऐसे मामले जहां पितृत्व का मुद्दा केवल विवाद के लिए आकस्मिक है, कुछ मामलों में पहचान के संकट से पीड़ित बच्चे में भी योगदान कर सकता है। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि कुछ बच्चे, हालांकि विवाह के निर्वाह के दौरान और विवाहित जोड़े की इच्छा और सहमति से पैदा हुए हैं, हो सकता है कि शुक्राणु दान से जुड़ी प्रक्रियाओं के माध्यम से गर्भधारण किया गया हो, जैसे कि अंतर्गर्भाशयी।

गर्भाधान (आई. यू. आई.), इन विट्रो निषेचन (आई. वी. एफ.)। ऐसे मामलों में बच्चे का डीएनए परीक्षण भ्रामक परिणाम दे सकता है। परिणाम एक बच्चे में माता-पिता के प्रति अविश्वास की भावना विकसित कर सकते हैं, और अपने जैविक पिता की खोज करने में असमर्थता के कारण निराशा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने जैविक पिता का पता लगाने के लिए एक बच्चे की खोज शुक्राणु दाता की गुमनामी के अधिकार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। इस तरह के कारकों को ध्यान में रखते हुए, एक माता-पिता, बच्चे के सर्वोत्तम हित में, बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करने का विकल्प चुन सकते हैं। डीएनए परीक्षण के लिए बच्चा। यह गोपनीयता के अधिकार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है कि किसी व्यक्ति को गर्भ धारण करने के लिए अपनाई गई चिकित्सा प्रक्रियाओं का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।

माता-पिता के इनकार करने के कई कारण हो सकते हैं, और इसलिए, धारा 114 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना विवेकपूर्ण नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम, प्रत्येक मामले में जहां माता-पिता बच्चे को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन करने से इनकार करते हैं।

इसलिए, यह आवश्यक है कि केवल असाधारण और योग्य मामलों में, जहां इस तरह का परीक्षण हल करने के लिए अपरिहार्य हो जाता है विवाद, न्यायालय इस तरह के परीक्षण का निर्देश दे सकता है। इसके अलावा, संचालन करने के लिए एक निर्देश

एक बच्चे के डी. एन. ए. परीक्षण का आदेश शायद ही कभी दिया जाना चाहिए, उन मामलों में जहां एक बच्चे का पितृत्व सीधे मुद्दे में नहीं है, लेकिन केवल कार्यवाही के लिए संपार्श्विक है, जैसे कि तत्काल मामले में।

निष्कर्ष -

23. ' अवैध '-एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति को शर्मसार करता है।

विवाह से बाहर पैदा होना, अपनी पहचान पर छाया डालता है। समय बदलता है और दृष्टिकोण बदल सकते हैं, लेकिन अवैध होने के सामाजिक कलंक के साथ बड़े होने का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अदालतों को बच्चे की वैधता को बनाए रखने की ओर झुकाव होना चाहिए जब तक कि तथ्य [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दुख्तर जहां बनाम मोहम्मद फारूक, (1987) 1 एस. सी. सी. 624 के अनुसार, वे इतने बाध्यकारी और दृढ़ हैं कि अनिवार्य रूप से एक निष्कर्ष की गारंटी देते हैं कि बच्चे को पिता से पैदा नहीं किया जा सकता था और बच्चे के इस तरह के वैधता के परिणामस्वरूप पिता के साथ अन्याय होगा।

24. एक बच्चे की अवैधता के बारे में प्रश्न, केवल व्यभिचार या बेवफाई के आधार पर विवाह के विघटन के दावे के लिए आकस्मिक हैं।

व्यभिचार को साबित करने के लिए, नियमित आधार पर डी. एन. ए. परीक्षणों को आयोजित करने की अनुमति देना, इस उक्ति को फिर से परिभाषित करने के बराबर होगा, जिसका अर्थ है, पिता वह है जिसे

विवाह इंगित करते हैं। व्यभिचार और बेवफाई के आरोपों से निपटने के दौरान, बच्चे के डी. एन. ए. परीक्षण के लिए अनुरोध, न केवल प्रतिस्पर्धा करता है

धारा 112 के तहत अनुमान, लेकिन शारीरिक स्वायत्तता की अनिवार्यता के साथ भी संघर्ष करता है।

25. एक अन्य पहलू जिस पर तत्काल मामले में विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या तलाक की कार्यवाही में न्यायसंगत निर्णय के लिए, एक डीएनए परीक्षण है विशेष रूप से आवश्यक। यह ऐसा मामला नहीं है जहां डीएनए परीक्षण ही एकमात्र है।

माँ के व्यभिचार के बारे में सच्चाई का मार्ग। यदि किसी कार्यवाही में बच्चों का पितृत्व मुद्दा है, तो सच्चाई स्थापित करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण ही एकमात्र मार्ग हो सकता है। हालाँकि, हमारे विचार में, वर्तमान में ऐसा नहीं है मामला। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत उपलब्ध निर्णायक अनुमान का खंडन करने के लिए डी. एन. ए. परीक्षण के साक्ष्य की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब 'पहुंच' से जुड़ी मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ हों, जिनका उदारता से उपयोग नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस अदालत ने दीपानविता राय में आगाह किया था।

26. प्रत्यर्थी-पति का मामला यह है कि यदि डी. एन. ए. परीक्षण की अनुमति दी जाती है और उसी से पता चलता है कि वह "एक्स" का जैविक पिता नहीं है, तो यह साबित होगा कि अपीलार्थी-पत्नी ने व्यभिचार किया था। हम निम्नलिखित कारणों से व्यभिचार साबित करने के लिए प्रतिवादी-पति द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं:

यह विवाद में नहीं है कि मास्टर "एक्स", बेटे को कहा गया है

आई.

अपीलार्थी की पत्नी का जन्म वर्ष 2013 में हुआ था। डी. एन. ए. परीक्षण, का उपयोग एक दशक पहले या बाद में मास्टर "एक्स" के जन्म के बाद हुई बेवफाई को स्थापित करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में नहीं किया जा सकता है।

ii.

वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, हम असमर्थ हैं

यह स्वीकार करें कि डी. एन. ए. परीक्षण ही एकमात्र तरीका होगा जिससे मामले की सच्चाई स्थापित की जा सकती है। प्रत्यर्थी पति ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उसके कब्जे में PARN AJINKYA FIRODIA v है।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[बी. वी. नागरत्ता, जे.]

कॉल रिकॉर्डिंग/प्रतिलेख और अपीलार्थी की दैनिक डायरी, जिसे अपीलार्थी की बेवफाई साबित करने के लिए कानून के अनुसार बुलाया जा सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि

हम तक कि प्रत्यर्थी ऐसे साक्ष्य के आधार पर एक मामला बनाने का प्रयास करने की स्थिति में है, जैसे कि अपीलार्थी की ओर से व्यभिचार/बेवफाई। प्रतिवादी द्वारा कोई याचिका नहीं उठाई गई है-यहाँ पति

iii.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को हटाने के लिए गैर-पहुंच के रूप में। इसलिए, कोई प्रथम दृष्टया नहीं

प्रतिवादी द्वारा मामला बनाया गया है जो मास्टर "एक्स" का डीएनए परीक्षण करने के निर्देश को उचित ठहराएगा।

तत्काल मामले में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

iv.

मास्टर "एक्स" की वैधता या पितृत्व के संबंध में और इसमें अपीलार्थी के संबंध में, मास्टर "एक्स" को पितृत्व परीक्षण के अधीन करने से इनकार करने पर। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा मास्टर "एक्स" को पितृत्व परीक्षण के अधीन करने से इनकार करने पर, कोई प्रतिकूल नहीं होगा।

कथित व्यभिचार के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है

इसमें अपीलार्थी का भाग उठाया जा सकता है। हमारे विचार में, व्यभिचार के आरोप को उत्तरदाता द्वारा मास्टर "एक्स" के पितृत्व के मुद्दे पर साबित किया जाना चाहिए।

27. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। नतीजतन, बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय की तारीखनवंबर, 2021 और परिवार न्यायालय, पुणे का आदेश दिनांक 12 तारीख

सेंट, 2021, अलग रखे गए हैं।

वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपील की लागत 1 लाख रुपये है जो प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को देय है। आज एक महीने की अवधि के भीतर परिवार न्यायालय के समक्ष भुगतान किया जाएगा।

बी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. जबकि मैं अच्छी तरह से तैयार की गई राय से पूरी तरह सहमत हूँ।

विद्वान बहन माननीय न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ता, मैंने सोचा

इस मामले के पहलुओं पर थोड़ा अधिक जोर देने की आवश्यकता है। इसलिए एक खाए हुए लेकिन सहमत राय।

2. जैसा कि हमने अपने विद्वानों द्वारा दिए गए तथ्यों के वर्णन से देखा है

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना-[2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी के साथ अपीलार्थी की शादी हुई

23.11.2005 पर।

फिर प्रतिवादी ने निजी तौर पर नवंबर 2016 में डीएनए लैब्स इंडिया से दूसरे बच्चे का डीएनए परीक्षण किया, जिसे आईएसओ 17025 प्रमाणित, ए2 एलए और एनएटीए मान्यता प्राप्त एजेंसी कहा जाता है। इसके बाद प्रतिवादी ने आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की

व्यभिचार, जून 2017 में।

तलाक की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने नवंबर 2020 में एक आवेदन दायर किया जिसमें दूसरे बेटे को डी. एन. ए. परीक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

सरकारी केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला।

3. पारिवारिक न्यायालय ने प्रत्यर्थी पति द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की, जिससे पत्नी को मजबूर होना पड़ा उपरोक्त अपील के साथ आएंगे, यह तर्क देते हुए कि धारा 112 के तहत

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 1, विवाह के दौरान जन्म वैधता का निर्णायक प्रमाण है और न्यायालय द्वारा इसे गलत साबित करने के लिए किसी भी साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह विशेष रूप से तब होता है जब विवाह के पक्षों को उस समय के दौरान एक-दूसरे तक पहुंच थी जब बच्चे का जन्म हो सकता था।

4. प्रत्यर्थी-पति के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल का मुख्य तर्क यह है कि प्रत्यर्थी बच्चे की वैधता पर भी सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि अपीलकर्ता पत्नी के खिलाफ व्यभिचार का आरोप लगा रहा है और इसलिए, पत्नी द्वारा बच्चे का डीएनए परीक्षण करने से इनकार करने पर, अपीलकर्ता-पत्नी के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (एच) के तहत एक अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उनका तर्क है कि मामले में जो लागू होता है, वह धारा 112 नहीं बल्कि धारा है

1 संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम" या "अधिनियम", जैसा भी मामला हो सकता है, ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरोदिया बनाम।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

114 (ज) और यदि अपीलार्थी इच्छुक नहीं है तो न्यायालय को बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्त विवाद के आलोक में, दो पहलू, मेरे

राय के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वे हैं (i) के बीच की परस्पर क्रिया

साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 और 114 (एच); और (ii) न्याय के पैमाने में संतुलन को झुकाने के अधिकार किसके हैं?

साक्ष्य की धारा 112 और 114 (एच) के बीच अंतःक्रिया

अधिनियम

6. साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 "अनुमान लगा सकते हैं", "अनुमान लगाएंगे" और "निर्णायक प्रमाण" अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है। धारा 4 इंगित करती है

ऐसे तथ्य में, यह दूसरे पक्ष पर निर्भर करता है कि वह अनुमान का खंडन करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करे। जहाँ कहीं भी अधिनियम "मान लेगा" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, जब तक इसका खंडन नहीं किया जाता, तब तक न्यायालय के पास तथ्य का अनुमान लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जहाँ भी अधिनियम "निर्णायक प्रमाण" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, न्यायालय इसे गलत साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य देने की भी अनुमति नहीं दे सकता है।

7. साक्ष्य अधिनियम में "मान लिया जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

धारा 79 में प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता के संबंध में

दस्तावेजों से।

सबूतों से।

राजपत्रों, समाचार पत्रों, संसद के अधिनियमों आदि की वास्तविकता के संबंध में धारा 81 में।

धारा 81 ए में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक की वास्तविकता के संबंध में

आधिकारिक राजपत्र होने का तात्पर्य रखने वाला अभिलेख।

इंग्लैंड में स्वीकार्य दस्तावेजों के संबंध में धारा 82 में

धारा 83 में मानचित्रों या बनाई गई योजनाओं की सटीकता के संबंध में सरकार के अधिकार से।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 84 में प्रत्येक पुस्तक की वास्तविकता के संबंध में

कुछ अपराधों के संबंध में धारा 111 क में।
क्षेत्र के हस्तांतरण के संबंध में धारा 113 में।

धारा 113 ख में दहेज मृत्यु के संबंध में।

धारा 114 ए में कुछ मामलों में सहमति के अभाव के संबंध में
बलात्कार के लिए मुकदमा।

8. साक्ष्य अधिनियम में "अनुमान लगाया जा सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

धारा 86 में न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के संबंध में
भारत के अलावा अन्य देशों में।

धारा 87 में लेखक, प्रकाशक और पुस्तकों, मानचित्रों और चार्ट के प्रकाशन के स्थान और समय
के संबंध में, जिसके लिए निम्नलिखित मामलों पर जानकारी के लिए एक संदर्भ बनाया गया है -

धारा 88 में टेलीग्राफ संदेशों के संबंध में।
धारा 88 ए में इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में।

धारा 90 में उन दस्तावेजों के संबंध में जो तीस वर्ष के हैं।

पुराना।

धारा 90 ए में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संबंध में जो हैं -

पाँच साल की उम्र।

धारा 113 ए में आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में

विवाहित महिला।

धारा 114 में कुछ तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में।

9. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि साक्ष्य अधिनियम में विवाह के दौरान जन्म की स्मृति को शामिल नहीं
किया गया है, या तो एक तथ्य की श्रेणी के तहत "अनुमानित किया जा सकता है" या एक तथ्य की श्रेणी के
तहत जो "ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरोदिया बनाम।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

अनुमान लगाया जाए "। इसके विपरीत, अधिनियम विवाह के दौरान जन्म की वैधता के "निर्णायक प्रमाण" के रूप में रखता है। लेकिन धारा 112 एक खिड़की खुली रखती है, जो शादी के लिए एक पक्ष को सक्षम बनाती है जो बच्चे की वैधता पर सवाल उठाता है, यह दिखाने के लिए कि उसकी दूसरे तक कोई पहुंच नहीं थी, जब बच्चा पैदा हो सकता था।

10. हमने देखा है कि धारा 4 के तहत, जब अधिनियम द्वारा एक तथ्य को निर्णायक प्रमाण घोषित किया जाता है, तो न्यायालय उस तथ्य के प्रमाण पर करेगा।

11. धारा 4 और धारा 112 के संयुक्त अध्ययन से पता चलेगा कि एक बार पक्ष बच्चे के जन्म की वैधता पर सवाल उठाएगा। यह दर्शाता है कि विवाह के पक्षों की एक-दूसरे तक कोई पहुंच नहीं थी, तो धारा 112 का लाभ धारा का आह्वान करने वाले पक्ष को उपलब्ध नहीं है

112. दूसरे शब्दों में, यदि विवाह का कोई पक्ष यह स्थापित करता है कि विवाह के लिए दूसरे पक्ष तक कोई पहुंच नहीं थी, तो निर्णायक निर्णय की ढाल

प्रमाण अनुपलब्ध हो जाता है। यदि इसके विपरीत, ऐसा पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि उसकी विवाह के लिए दूसरे पक्ष तक कोई पहुंच नहीं थी, तो धारा 112 की ढाल दूसरे पक्ष को इस हद तक बचाती है कि धारा 4 में निहित निषेध को देखते हुए उसे किसी भी प्रमाण से छेदा नहीं जा सकता है।

12. इसके विपरीत, धारा 114, जिस पर प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल द्वारा भारी निर्भरता रखी गई है, केवल संबंधित है।

13. जैसा कि पहले बताया गया है, जहां भी अधिनियम "अनुमान लगा सकता है" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, यह केवल वैकल्पिक है और न्यायालय के लिए इस तरह के तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाना अनिवार्य नहीं है। कि यह केवल वैकल्पिक स्टैंड है (i) धारा 114 के तहत चित्रण; और (ii) उन चित्रणों की आगे की व्याख्या। इस स्तर पर [2023] 4 एस. सी. आर. निकालना उपयोगी हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 114; (ii) धारा 114 के तहत चित्रण; और (iii) उन चित्रणों का उल्लेख, जो सभी इस प्रकार हैं:

" 114. न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है। द.

न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है जिसे वह संभावित मानता है।

हुआ है, सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक घटनाएँ, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय,

विशेष मामले के तथ्यों के साथ उनका संबंध।

दृष्टांत

न्यायालय अनुमान लगा सकता है कि

(क) कि चोरी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति के पास चोरी का सामान है, वह या तो चोर है या उसे यह जानते हुए सामान मिल गया है कि वह चोरी हो गया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब न दे सके;

(ख) कि एक साथी श्रेय के योग्य नहीं है, जब तक कि वह

सामग्री विवरण में पुष्टि की गई;

(ग) कि एक विनिमय विधेयक, स्वीकार या समर्थित, स्वीकार किया गया था।

या अच्छे विचार के लिए समर्थित;

(घ) वह वस्तु या स्थिति जिसे दिखाया गया है -

उस अवधि से कम अवधि के भीतर अस्तित्व में है जिसके भीतर ऐसी चीजें या चीजों की स्थिति आमतौर पर अस्तित्व में नहीं रहती है, अभी भी अस्तित्व में है;

(ई) कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं;

(छ) वह साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जा सकता है और जो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यदि प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे रोकने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होगा।

(ज) कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह कानून द्वारा मजबूर नहीं है, तो उत्तर, यदि दिया जाता है, तो यह होगा:

उसके लिए प्रतिकूल;

(i) कि जब कोई दायित्व बनाने वाला दस्तावेज बाध्यकारी के हाथों में होता है, तो दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है।

लेकिन न्यायालय को ऐसे तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा जैसे -

निम्नलिखित, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या ऐसे सिद्धांत उससे पहले के विशेष मामले पर लागू होते हैं या नहीं: उदाहरण के रूप में (क)-एक दुकानदार के नोट में चोरी होने के तुरंत बाद एक चिह्नित रुपया होता है, और वह उसके कब्जे का हिसाब नहीं दे सकता है।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

विशेष रूप से, लेकिन अपने व्यवसाय के दौरान लगातार रुपये प्राप्त कर रहा है; जहां तक चित्रण (बी) का संबंध है-ए, उच्चतम चरित्र वाले व्यक्ति, पर लापरवाही के कार्य से एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए मुकदमा चलाया जाता है।

कुछ यंत्रों की व्यवस्था करना। बी, समान रूप से अच्छे चरित्र का व्यक्ति, जिसने भी व्यवस्था में भाग लिया, ठीक से वर्णन करता है कि क्या किया गया था, और आम लापरवाही को स्वीकार करता है और समझाता है

ए और स्वयं;

जहां तक चित्रण (बी) की बात है-एक अपराध कई लोगों द्वारा किया जाता है।

जहां तक दृष्टांत (ग) की बात है-ए, विनियम पत्र का दराज़, एक व्यवसायी था। बी, स्वीकारकर्ता, युवा और अज्ञानी व्यक्ति था, जो पूरी तरह से ए के प्रभाव में था; उदाहरण के लिए (घ)-यह साबित होता है कि पाँच साल पहले एक नदी एक निश्चित मार्ग से बहती थी, लेकिन यह ज्ञात है कि बाढ़ आई है।

उस समय से जो अपना मार्ग बदल सकता है; जहां तक दृष्टांत (ई) का संबंध है-एक न्यायिक अधिनियम, जिसकी नियमितता प्रश्रुत है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था;

उदाहरण (च) के बारे में सवाल यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था। यह पोस्ट किया गया दिखाया गया है, लेकिन सामान्य पाठ्यक्रम

गड़बड़ी के कारण पद बाधित हो गया था;

उदाहरण के रूप में (छ)-एक व्यक्ति एक दस्तावेज पेश करने से इनकार कर देता है जो कम महत्व के अनुबंध पर होगा जिस पर उस पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति की भावनाओं और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

उसका परिवार;

जिसके संबंध में यह पूछा जाता है; जहां तक दृष्टांत का संबंध है (i)-एक बंधन बाध्यकारी के कब्जे में है, लेकिन मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसके पास हो सकता है

चुरा लिया। "[2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. जैसा कि दृष्टांतों को दिए गए विवरण से देखा जा सकता है, न्यायालय को किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाने या न लगाने का निर्णय लेते समय कुछ अतिरिक्त तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या ऐसे सिद्धांत विशेष मामले में लागू होते हैं या नहीं।

15. यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 114 के तहत (ए) से (आई) तक नौ चित्रण हैं। उन दृष्टांतों के तुरंत बाद, उन दृष्टांतों की व्याख्या इन शब्दों से शुरू होती है: लेकिन न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या ऐसे सिद्धांत उसके समक्ष विशेष मामले पर लागू होते हैं या नहीं।

16. उदाहरण के लिए, धारा 114 के तहत चित्रण (एच) लेते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देता है जिसके लिए उसे मजबूर नहीं किया जाता है

कानून द्वारा उत्तर देने के लिए, न्यायालय यह मान सकता है कि यदि उत्तर दिया जाता है, तो वह उसके लिए प्रतिकूल होगा। लेकिन इलस्ट्रेशन (एच) का विवरण कहता है

कि (ज) के तहत उक्ति पर विचार करते समय, न्यायालय को इस बात पर उचित ध्यान होगा कि क्या व्यक्ति द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करना, इस तथ्य के कारण है कि उत्तर उस मामले से असंबद्ध मामलों में उसे नुकसान पहुंचा सकता है जिसके संबंध में यह पूछा जाता है।

17. दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थिति से निपटने के दौरान जहां धारा 114 के तहत चित्रण (एच) के संदर्भ में एक धारणा उठाई जानी चाहिए, अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या व्यक्ति द्वारा जवाब देने से इनकार करना, इस डर के कारण है कि जवाब से मुद्दे के मामले के संबंध में उसके लिए प्रतिकूल परिणाम आ सकता है या इस डर के कारण है कि इस तरह के जवाब से उसे किसी ऐसे मामले में नुकसान हो सकता है जिससे उसका कोई संबंध नहीं है।

18. धारा 4, 112 और 114 की उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम वरिष्ठ विद्वान श्री कपिल सिब्बल के मुख्य तर्क का परीक्षण करें।

प्रत्यर्थी के लिए वकील-पति कि प्रत्यर्थी पति का प्रयास यह दिखाने के लिए इतना अधिक नहीं है कि उसने दूसरे बच्चे का पिता नहीं था, बल्कि केवल यह दिखाने के लिए है कि अपीलार्थी व्यभिचार में रह रहा था और इस मामले में जो काम आता है वह केवल धारा 114 है न कि धारा 112। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-पति डीएनए परीक्षण के परिणाम की परवाह किए बिना, दूसरे बच्चे को अपने रूप में स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह अपीलकर्ता-पत्नी के लिए खुला है कि वह बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण न करे, भले ही न्यायालय उसी का आदेश दे, लेकिन यदि अपीलकर्ता बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण न करने का विकल्प चुनता है, तो न्यायालय धारा 114 (एच) के संदर्भ में एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।

विद्वान परणा अजिंक्या फिरुडिया बनाम के अनुसार। अजिंक्य अरुण फिरुडिया

[वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

आर वकील, ऐसा प्रतिकूल निष्कर्ष पितृत्व बच्चे के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल अपीलार्थी के व्यभिचारी आचरण के बारे में होना चाहिए।

19. प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि इस तरह का प्रतिकूल निष्कर्ष, बच्चे के पितृत्व के बारे में नहीं, बल्कि उसके व्यभिचारी आचरण के बारे में कानून में अनुमत है।

निर्णय के अंतिम दो अनुच्छेदों पर भारी निर्भरता

एनविता रॉय बनाम रोनोब्रतो रॉय 2. ये परिच्छेद इस प्रकार हैं:

" 17. इस मामले में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह अपीलार्थी पत्नी की कथित बेवफाई के संबंध में है। उत्तरदाता

पति ने बेवफाई का आरोप लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर याचिका में स्पष्ट और स्पष्ट दावे किए हैं। वह उस व्यक्ति का नाम रखने की हद तक चला गया है जो

अपीलार्थी पत्नी से पैदा हुए पुरुष बच्चे का पिता था। यह बेवफाई के अपने आरोप को साबित करने की प्रक्रिया में है कि प्रतिवादी पति ने डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष एक आवेदन किया था जो यह स्थापित करेगा कि उसने अपीलार्थी पत्नी से पैदा हुए पुरुष बच्चे का पिता था या नहीं। प्रत्यर्थी को लगता है कि उसके लिए डीएनए परीक्षण के माध्यम से (अपीलार्थी पत्नी की बेवफाई के) उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करना ही संभव है। हम उनसे सहमत हैं। हमारे विचार में, लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण के लिए, प्रतिवादी पति के लिए अभिवचनों में किए गए दावों को स्थापित और पुष्टि करना असंभव होगा। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश, जैसा कि यहाँ ऊपर निकाला गया है, पूरी तरह से उचित था। डी. एन. ए. परीक्षण सबसे वैध और वैज्ञानिक रूप से सही साधन है, जिसका उपयोग पति अपनी बेवफाई के दावे को स्थापित करने के लिए कर सकता है। इसे साथ ही पत्नी के लिए भी सबसे प्रामाणिक, सही और सही साधन के रूप में लिया जाना चाहिए, ताकि वह प्रतिवादी पति द्वारा किए गए दावों का खंडन कर सके और यह स्थापित कर सके कि वह विश्वासघाती, व्यभिचारी या विश्वासघाती नहीं थी। यदि अपीलार्थी पत्नी सही है, तो वह

यह सिद्ध हो जाएगा।

18. हालाँकि, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, एक चेतावनी दर्ज करना उचित और उचित समझेंगे, जिससे अपीलार्थी पत्नी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने या उसकी अवहेलना करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें डी. एन. ए. परीक्षण आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यदि वह उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को स्वीकार करती है,

365 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. एन. ए. परीक्षण निर्णायक रूप से सच्चाई का निर्धारण करेगा

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में अनुध्यात प्रकृति का अनुमान लगाना, विशेष रूप से, उसके चित्रण (ज) के संदर्भ में। धारा 114, जैसा कि ऊपर उल्लिखित चित्रण (एच) भी है, का उल्लेख किया जा रहा है यहाँ नीचे निकाला गया है:

“ 114. न्यायालय कुछ के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है

तथ्य। न्यायालय प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक व्यवहार के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है, जिसके बारे में वह सोचता है कि ऐसा हुआ होगा।

और निजी व्यवसाय, विशेष के तथ्यों के संबंध में

मामला "।

" चित्रण (एच)-कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह कानून द्वारा मजबूर नहीं है, तो अगर जवाब दिया जाता है, तो यह उसके लिए प्रतिकूल होगा।

इस पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार को यथासंभव संरक्षित करने के लिए अपनाया गया है। बेशक, बलिदान किए बिना

न्याय का कारण। उपरोक्त पाठ्यक्रम को अपनाकर, का मुद्दा

साक्ष्य की धारा 112 के तहत परिकल्पित धारणा को स्पष्ट रूप से बाधित किए बिना, केवल बेवफाई का निर्धारण किया जाएगा। एकट करें। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, निस्संदेह यह मुद्दा है

वैधता भी संयोग से शामिल होगी।

20. श्री कपिल सिब्बल ने भी भारी निर्भरता रखी है

आर में निर्णय के पैराग्राफ 79 पर प्रतिवादी के लिए वकील

दा बनाम धर्मपाल '। वह इस प्रकार है:

" 79. यदि अदालत द्वारा पारित आदेश के बावजूद, कोई व्यक्ति इस तरह की चिकित्सा जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए एक मजबूत मामला बनाया जाएगा। की धारा 114

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक अदालत को एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में भी सक्षम बनाता है यदि पक्ष संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है।

उसकी शक्ति और अधिकार "।

21. लेकिन हम नहीं जानते कि धारा 112 और धाराओं का मिश्रण कैसे संभव है। धारा 112 कुछ ऐसी चीज़ से संबंधित है जहाँ

5) 4 एस. सी. सी. 493 ए. पी. ए. आर. एन. ए. अजिंक्य फिरोदिया बनाम। अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

किसी तथ्य को निर्णायक प्रमाण के रूप में लिया जाता है, बिना किसी विवाद करने वाले पक्ष के लिए उसे गलत साबित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की कोई संभावना के। धारा 112 के लाभ से किसी अन्य व्यक्ति को वंचित करने के लिए एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र बचने का मार्ग या आपातकालीन निकास, यह दिखाने के लिए है कि विवाह के पक्षों की उस समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चा पैदा हो सकता था। धारा 114 का न तो कोई लेना-देना है और न ही इसका संबंध धारा 112 द्वारा व्यवहार की गई वैधता के निर्णायक प्रमाण से है। धारा 112 और धारा 114 दोनों अलग-अलग विभागों के अंतर्गत आती हैं। अनुभाग में स्वयं "अनुमान" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। 112. धारा 112 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निर्णायक प्रमाण" है। इसलिए, धारा 4 के आधार पर, इसे गलत साबित करने के उद्देश्य से कोई सबूत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. जैसा कि हमने कहीं और संकेत दिया है, यदि विवाह के पक्षों में से एक यह दर्शाता है कि उस समय जब बच्चा पैदा हो सकता था, उस समय उसकी दूसरे तक पहुंच नहीं थी, तो धारा 112 स्वयं आकर्षित नहीं होती है। इसके विपरीत, यदि पक्षों के पास प्रासंगिक समय पर एक-दूसरे तक पहुंच है, तो वैधता से संबंधित प्रश्न का भाग्य सील कर दिया जाता है।

23. हम एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि धारा 112 पत्नी के कथित व्यभिचार के लिए भी ढाल के रूप में कार्य करती है। हम केवल इतना कहते हैं कि धारा 112 के कानूनी प्रभाव को नष्ट करने वाली किसी भी चीज़ का उपयोग प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि ऐसा ही एक और परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। 24. हाथ में मामले में, परिवार न्यायालय के समक्ष तलाक के लिए अपनी याचिका में प्रतिवादी का निवेदन यह है कि दूसरा बच्चा

मास्टर "एक्स" का जन्म 17.7.2013 पर हुआ था और प्रतिवादी को इसमें अपीलार्थी के कथित व्यभिचारी व्यवहार के बारे में केवल 14.9.2016 पर पता चला था। तलाक के लिए अपनी याचिका के पैराग्राफ 23 में, प्रतिवादी ने निम्नानुसार अनुरोध किया:

" 23. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 1 के व्यभिचार और क्रूर व्यवहार को माफ नहीं किया है। याचिकाकर्ता को उसके व्यभिचारी कृत्य का पता चलने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हालांकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नहीं। 1 एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं। 1 याचिकाकर्ता के दिन से शयनकक्ष साझा नहीं किया है और कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं

उत्तरदाता संख्या 1 ". [2023] 4 एस. सी. आर. के व्यभिचार की खोज की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. उत्तरदाता की इस प्रभाव से ऊपर निकाली गई अभिवचन कि सितंबर 2016 के बाद, उसके अपीलकर्ता-पत्नी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि कम से कम उस समय जब बच्चा पैदा हुआ था और तीन साल की पूरी अवधि के लिए उसकी पत्नी तक पहुंच थी।

उसके बाद भी। इसलिए, धारा 112 के तहत निर्णायक सबूत वास्तव में इस मामले में काम में आया है।

26. प्रत्यर्थी के तर्क में एक और भ्रान्ति है। यह.

प्रत्यर्थी का तर्क है कि वह केवल धारा 114 (एच) के तहत पत्नी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की मांग कर रहा है, जब पत्नी ने बच्चे को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन करने से इनकार कर दिया हो। लेकिन जिस स्तर पर पत्नी बच्चे को डी. एन. ए. के अधीन करने से इनकार कर सकती है, वह अदालत के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही उत्पन्न होगी कि डी. एन. ए. परीक्षण किया जाना चाहिए।

आदेश दिया। सरल शब्दों में कहें तो इस प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं -

अर्थात्, (i) डी. एन. ए. परीक्षण का आदेश दिया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर न्यायालय द्वारा विचार; (ii) इस तरह के विचार के बाद डी. एन. ए. परीक्षण का निर्देश देने वाला आदेश पारित करना; और (iii) इस तरह से पारित आदेश का पालन करने या न करने का पत्नी का निर्णय। प्रत्यर्थी को पहले बाहरी बाड़ को पार करना चाहिए, अर्थात् डीएनए परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है या नहीं। यह तभी होता है जब वह अदालत को डी. एन. ए. परीक्षण का आदेश देने के लिए आश्वस्त करता है और सफलतापूर्वक परीक्षण सुनिश्चित करता है। आदेश दें कि वह आदेश का पालन करने के लिए पत्नी की इच्छा के संबंध में आंतरिक बाड़ पर जा सकता है। यह केवल उस स्तर पर है कि प्रतिवादी, यदि बिल्कुल भी हो, तो धारा 114 (एच) के तहत शरण ले सकता है।

27. लेकिन आज, हम वास्तव में इस मामले में बाहरी बाड़ पर हैं, यह निर्णय लेते हुए कि क्या डीएनए परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। इसलिए,

प्रतिवादी बाहरी बाड़ को पार करके आंतरिक बाड़ पर नहीं कूद सकता है।

28. धारा 114 (एच) के तहत अनुमान पर आते हुए, प्रतिवादी का तर्क स्पष्ट रूप से गलत है। एक प्रतिकूल अनुमान, कानून में,

केवल उस व्यक्ति के खिलाफ खींचा जा सकता है जो किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है। हाथ में मामले में, अपीलार्थी की दोहरी भूमिका है, अर्थात्, प्रत्यर्थी की पत्नी की और मास्टर "एक्स" की माँ की। यदि अपीलार्थी अपने लिए लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ करता है या करने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन एक माँ और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में उसकी क्षमता में यदि अपीलार्थी बच्चे के हितों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण करने से इनकार करती है, तो उसके खिलाफ व्यवहार का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने से इनकार करके, वह वास्तव में बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा कर रही है। बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए, अपीलार्थी-पत्नी को पुरस्कृत किया जा सकता है, लेकिन अपर्णा अजिंक्य फिरुडिया V से दंडित नहीं किया जा सकता है।

अजिंक्य अरुण फिरोदिया

[वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

एक प्रतिकूल अनुमान। धारा 114 (एच) का सहारा लेकर, प्रतिवादी अपीलार्थी को पकड़-22 की स्थिति में नहीं डाल सकता है।

29. इसलिए, धारा 114 (एच) का उस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां एक माँ बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने से इनकार करती है। होना ही है।

याद रखें कि बच्चे पर डी. एन. ए. परीक्षण करने का उद्देश्य मुख्य रूप से यह दिखाना है कि प्रतिवादी जैविक पिता नहीं था। एक बार जब वह तथ्य स्थापित हो जाता है, तो यह केवल एक परिणाम के रूप में सामने आता है कि अपीलार्थी एक व्यभिचारी संबंध में रह रहा था।

30. मुख्य उत्पाद के रूप में डी. एन. ए. परीक्षण से जो निकलता है, वह बच्चे का पितृत्व है, जिसे परीक्षण के अधीन किया जाता है। संयोगवश, पत्नी का व्यभिचारी आचरण भी उसी प्रक्रिया के माध्यम से एक उप-उत्पाद के रूप में स्थापित होता है। कहने के लिए कि पत्नी को अनुमति देनी चाहिए

बच्चे को डी. एन. ए. परीक्षण से गुजरना चाहिए, ताकि पति को उत्पाद और उप-उत्पाद दोनों का लाभ मिल सके या विकल्प के रूप में पत्नी को पति को उप-उत्पाद का लाभ लेने की अनुमति देनी चाहिए।

धारा 114, यदि वह बच्चे को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन नहीं करने का विकल्प चुनती है, तो वास्तव में शैतान और गहरे समुद्र के बीच का विकल्प पत्नी पर छोड़ देता है।

31. वास्तव में, इस प्रकार के मामलों में न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि धारा 114 में केवल "मे" शब्द का उपयोग किया गया है न कि "विल" शब्द का। इसलिए, धारा 114 के तहत चित्रण (एच) के स्पष्टीकरण में व्यक्त बाधाएं न्यायालय को बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाने के लिए मना कर सकती हैं।

32. इसलिए, हम प्रत्यर्थी के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि जिसे लागू करने की मांग की गई है वह केवल धारा 114 (एच) है न कि धारा 112।

न्याय के तराजू में संतुलन को झुकाने के अधिकार किसके हैं?

34. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आखिरकार प्रत्येक न्यायालय का प्रयास होना चाहिए - सच्चाई का पता लगाएं और मुकदमे के प्रत्येक पक्ष को सबसे अच्छा सबूत पेश करने का अधिकार है। पक्ष को सबसे अच्छा सबूत पेश करने में सक्षम बनाना, [2023] 4 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक हिस्सा। इसलिए, यह विद्वान द्वारा तर्क दिया जाता है वरिष्ठ वकील ने कहा कि बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराने से इनकार करने से प्रतिवादी के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन होगा। विवाद को मजबूत करने के लिए

कि किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार दूसरे के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार के अधीन होना चाहिए, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। बनाम प्रतिभूतियाँ और

भारतीय विनिमय बोर्ड & Anr.4

35. यद्यपि यह पहली नज़र में आकर्षक लग सकता है, उक्त तर्क का कोई कानूनी महत्व नहीं है। इन मामलों में एल. आई. विवाह के पक्षों के बीच होता है। यह विवाह के किसी एक पक्ष और उस बच्चे के बीच नहीं है जिसके पितृत्व पर सवाल उठाया जाता है। विवाह के पक्षकारों में से किसी एक को निष्पक्ष विचारण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, न्यायालय किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों और सर्वोत्तम हितों का त्याग नहीं कर सकता है, अर्थात् बच्चा। 36. इसलिए, मैं अपनी विद्वान बहन के साथ पूरे दिल से सहमत हूँ कि परिवार न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने बच्चे के डीएनए परीक्षण के लिए प्रतिवादी के आवेदन को अनुमति देने में गलती की थी।

इसलिए, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। तथापि, यह प्रत्यर्थी-पति को तलाक की याचिका में अपीलार्थी के खिलाफ उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य का नेतृत्व करने से नहीं रोकेगा।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

4 (2012) 10 एस. सी. सी. 603